प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ..सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो। यही सफलता का रहस्य है।

स्वामी शिवानंद सरस्वती

वर्ष-05, अंक - 36 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 08 जून 2023 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

हर अवैध धंधे को भाजपाई संरक्षण ही क्यों...?

भदु से दलाली और भानु का खास, सप्लायर से दल्ला बना गौरव, करने लगा दलाली

अलीराजपुर में बॉयो डीजल के अवैध धंधे में भदु का पार्टनर गुल्लु, रेत के धंधे में विशाल के लिए करता दलाली

माही की गूंज, संजय भटेवरा

झाबुआ। रेत माफियाओं के काले कारनामें और दलाली का मामला इन दिनों जोरों पर है। अफसरों के मुंह में हराम के टूकड़े नही डालने से उजागर हुई इस कहानी का अंत कहीं दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। लगभग एक सप्ताह तक चले रेत माफियाओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की गुत्थम गुत्था सुलझने का नाम नहीं ले रही है। रेत माफिया बिना रायल्टी के अवैध रेत का परिवहन करते है, यह सत्य है, लेकिन इन्हे बढ़ावा आखिर कौन देता है...? भाजपा नेता उर्फ रेत माफिया ने एसडीएम जैसे अधिकारी पर लाखों की अवैध वसूली का आरोप लगाया है, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि यह आरोप गलत हो। क्योंकि इस जिले में अफसरशाही इस तरह के कृत्य को अक्सर अंजाम देती रही है चाहे वह रेत माफिया हो, शराब माफिया हो या फिर कोई और माफिया। हर तरह के अवैध धंधों में अफसरों की भेंट पूजा, माफिया हमेशा से ही करते आए है। इस पूरे मामले में नेताओं और प्रशासन के बीच चल रही तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के सामने भी कई तरह की शिकायतें नेताओं के जरिए पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से नेताओं ने अफसरों की जमकर शिकायतें की। नेताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि, अधिकारी हमारी कोई बात को तवज्जो नहीं देते और ना ही अधिकारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई होती है। इसके उलट मुख्यमंत्री को सफाई देते हुए अधिकारियों ने कहा कि, नेता और कार्यकर्ता ठेकेदारी, सप्लायर्स और दूसरे अवैध कामों के लिए दबाव बनाते है। इन सारे शिकवे-शिकायतों में एक बात तो साफ है कि कोई भी दूध का धुला तो नहीं है। अधिकारियों की अगर बात मान लें तो यह तय है कि, सत्ता के पावर का इस्तेमाल कर भाजपाई मालामाल होना चाहते है। तो भाजपाईयों की शिकायत पर यह भी साफ होता है कि अधिकारी किसी भी अवैध धंधे को करने की छूट बिना कुछ लेन-देन के नहीं देना चाहते। मतलब साफ है ना खाएंगे ना खाने देंगे और अगर तुम खाओगे तो हमें भी हिस्सा चाहिए। अब शिवराजसिंह के लिए यह स्थिति ऐसी है कि, करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या...!

भाजपाई रेत माफिया और भाजपाई ही दलाल

चूंकि इस पूरे मामले में जो नाम उजागर हुए है वे लगभग सारे भाजपा से जुड़े नाम है। अलीराजपुर जिले के जिस रेत माफिया ने एसडीएम पर लाखों रुपयों की अवैध वसूली का आरोप लगाया है वह खुले तौर पर भाजपा की नुमाईंदगी करता है। वर्तमान में भदु पचाया की पत्नी जनपद सदस्य है तो इससे पहले भी नगर निकाय चुनाव में भाजपा की तरफ से हाथ आजमा चुका है। मतलब पूरा का पूरा पक्का भाजपाई। एसडीएम के अनुसार जब भदु पचाया की गाड़ी पकड़ी गई तब उसके पास गाड़ी में रायल्टी की रशीद नहीं थी। इसका मतलब भदु रेत का अवैध धंधा भाजपाई संरक्षण में करता है और बड़ा रेत माफिया है। इसके उलट इस पूरे मामले में एसडीएम के दलाल के नाम से मशहूर हुए गौरव की अगर पृष्ठ भूमि देखी जाए तो कहने को तो सप्लायर है मगर पूरी तरह से भाजपा से जुड़ा है और भानु भुरिया का खास माना जाता है। बताने वाले तो यह भी बताते है कि, दल्ला गौरव भाजपा जिलाध्यक्ष भानु भूरिया का अघोषित पीए ही है।

सत्ता किसी की भी रहे पर माफियाओं का अवैध कारोबार बरकरार रहेगा...

भदु अलीराजपुर से है तो भानु का पीए गौरव झाबुआ से। भदु पचाया की गाड़ी एसडीएम झाबुआ ने पकड़ी, भदु के मुनीम से फोन पर चर्चा की और भानु का पीए दल्ले गौरव से सर्किट हाउस में मुनीम की मुलाकात करवाई। लाखों रुपये का अवैध लेन-देन भदु पचाया के अनुसार हुआ। मतलब अवैध धंधे में अवैध लेने-देन दोनों ही भाजपाईयों के बीच हुआ। झाबुआई भाजपाई ने अलीराजपुर के भाजपाई की कब्र खोदी और लाखों रुपये की चपत लगा दी। इन सब के बीच एक प्रश्न फिर उभर कर सामने आता है कि, क्या वाकई में एसडीएम ने माफिया से अवैध वसूली की है...? या फिर एसडीएम और गौरव का सहारा लेते हुए गौरव के आका ने इस अवैध काली कमाई पर हाथ साफ किया हैं...? हालांकि इस बात की अभी तक कोई पुष्टी नहीं है, लेकिन रेत माफियाओं का यह मामला शांत नहीं हुआ तो यह तय है की प्याज के छिलके परत दर परत निकलेंगे ही। कुल मिलाकर बात यह है कि, इस पूरे मामले में सत्ता का जोर खुले रूप से दिखाई पड़ता नजर आ रहा है। माफियाओं की लाइन में सिर्फ भाजपाई ही खड़े दिखाई पड़ रहे है।

पिछले दिनों जिले में जलसंसाधन विभाग द्वारा बनाए जा रहे बैराजों का मामला भी भाजपाई खींचतान का शिकार हुआ था। अंदर खाने विभाग में चर्चाएं गर्मा गई थी। बाबूओं और सब इंजिनियरों की आपसी खुसुर-फुसुर ऐसी थी कि, जिले में भाजपाई सिर मोर ने 40 लाख रुपये की मांग की थी, जिसकी भरपाई न कर पाने के कारण ईई को रवानगी लेनी पड़ी थी। इन सारे मामलों के मद्दे नजर अब यह सवाल तो खड़ा होता ही है कि, हर अवैध धंधे को भाजपाई संरक्षण ही क्यों...?

गुल्लु भी है भाजपाई दलाल और अवैध धंधों का सरगना

दलालों की फहरिस्त भाजपा में लंबी होती जा रही है। हालांकि इन दलालों को किसी भी सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता मगर जिसकी सत्ता उसके हम तर्ज पर यह हमेशा ही सक्रिय नजर आए है और आते रहेंगे। रेत माफियाओं के इस खेल के उजागर होने के बाद कई तरह के राज खुलकर सामने आ चुके है। वैसे तो रेत माफियाओं का यह काला कारोबार कई दशकों से अलीराजपुर-झाबुआ जिले में चलता आ रहा है। इन्ही रेत माफियाओं के दम पर पलने वाले दल्ले भी इन्ही की तरह खूब फलफूल रहे है। माही की गूंज ने अपने पिछले अंक में दल्लों की आपसी लड़ाई का ऑडियो जारी किया था। इस ऑडियों में कई बड़े नेताओं के नाम उजागर हुए थे। अलीराजपुर जिले में रेत के इस अवैध करोबार में सबसे बड़ा दल्ला गुल्लु है जिसकी तूती तमाम माफियाओं में बोलती है। यह दल्ला जोबट की भाजपा विधायक सुलोचना रावत के पुत्र विशाल रावत का खासम खास है। रेत के अवैध परिवहन की गाड़ियों से वसूली कर अपने आकाओं तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा गुल्लु का ही है। झाबुआ जिले में, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेष दुबे को इसका मायबाप माना जाता है और सीधे तौर पर यह भी भाजपा से ही जुड़ा है।

गुल्लु कई अवैध धंधों में है संलिप्त

जोबट के विशाल रावत से दो जिस्म एक जान जैसे संबंध रखने वाला गुल्लु और भी कई अवैध धंधों में संलिप्त है। रेत माफियाओं से इसका गठजोड़ तो हम पहले ही उजागर कर चुके है। नाके बंदी कर रेत की अवैध गाड़ियों से खुलेआम उगरानी करने वाला गुल्लु बाहर की गाड़ी वालों से लाखों रुपये की बंदी हर महीनें लेता है। विशाल रावत के हर राजनीतिक खर्चे की पुर्ति भी गुल्लु ही रेत माफियाओं से उगरानी कर करता है। अब जबकि यह चुनावी साल है तो गुल्लु पर इस बात का भी ज्यादा दबाव है कि, विशाल भैया के चुनावी खर्च का इंतजाम करना है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि, इस बार जोबट सीट भाजपा के लिए टेढ़ी खीर होने वाली है। गुल्लु के बारे में गूंज ने जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाना शुरू की तो, कई चौकाने वाली बातें सामने आई है। मतलब गुल्लु रेत के अवैध कारोबार के अलावा भी कई अवैध धंधों में संलिप्त है।

भदु और गुल्लु की जोड़ी के बॉयोडीजल के अवैध धंधे भी

अलीराजपुर जिले के जिस भाजपाई नेता उर्फ रेत माफिया भदु पचाया का यह मामला गर्माया है। गुल्लु के उससे भी बहुत ही गजब के संबंध निकलकर सामने आए है। रेत माफिया भदु पचाया रेत के अवैध धंधे के साथ-साथ बॉयोडीजल का भी अवैध धंधा अलीराजपुर जिले में कर रहा है। भदु के बॉयोडीजल के इस काले धंधे में गुल्लु कुरैशी सीधे तौर पर पाटनर है। भदु और गुल्लु इस नकली बॉयोडीजल के अवैध धंधे में भी खूब जमकर चांदी काट रहे है। माही की गूंज ने झाबुआ जिले में पनपे बॉयोडीजल के अवैध धंधे का जमकर खुलासा किया था। इस कड़ी में कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी बेनकाब हुए थे। मगर अब यह नकली बॉयोडीजल माफिया अलीराजपुर जिले में भी भदु और गुल्लु के रूप में पनप रहे है। सुत्र तो यह भी बताते है कि, पड़ोसी जिले रतलाम में भी गुल्लु ने नकली बॉयोडीज के अवैध धंधे की नींव रखी थी, लेकिन किसी कारणवश गुल्लु की यहां दाल नहीं गल सकी। नतीजा यह हुआ कि गुल्लु को उल्टे पैर वापस रतलाम से रवानगी लेनी पड़ी।

गुल्लु सक्रिय भाजपाई तो गुड्डू सक्रिय कांग्रेसी

रेत और नकली बॉयोडीजल माफिया गुल्लु वैसे तो भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन इसके उलट गुल्लु का भाई रशीद उर्फ गुड्डू कांग्रेस का सक्रिय कर्ताकर्ता है। भाजपा और कांग्रेस में गुल्लु और गुड्डू का तालमेल एक अलग ही कहानी बनाता नजर आ रहा है। अलीराजपुर जिले में गुल्लु , विशाल रावत और भदु पचाया की शरण में है, तो झाबुआ जिले में पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेष दुबे का हाथ गुल्लु के सिर पर है। इसके उलट गुड्डू कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं में पेठ रखता है। मतलब सत्ता किसी की भी हो गुल्लु और गुड्डू अपनी तिकड़क से हमेशा अपने अवैध धंधों को चलाते ही रहेंगे। सुत्र बताते है कि, गुल्लु जितना जमीन पर है, गुड्डू उतना ही जमीन के अंदर। जैसे गुल्लु के अवैध धंधे है वैसे ही गुड्डू भी दूध का धुला नहीं है।

गुल्लु का भतीजा चलाता जुंऐ सट्टे के क्लब

गुल्लु यूं तो रेत और बॉयोडीजल के अवैध धंधे से काली कमाई कर रहा है, लेकिन इसके अलावा गुल्लु का भतीजा भी अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ में जुएं-सट्टे के क्लब चला रहा है। अपने इस जुएं-सट्टे के अवैध कारोबार को बचाने के लिए गुल्लु ने अपने भतीजे को नकली पत्रकार तक बना डाला है। बताते है गुल्लु ने अपने भतीजे को जिस सिखंडी पत्रकार के संरक्षण में पत्रकारिता सिखाने के लिए रखा है, वही सिखंडी पत्रकार, गुल्लु और उसके भतीजे का क्लब चलाने में संरक्षक और पार्टनर भी है। मतलब जुएं-सट्टे की काली कमाई में सिखंडी पत्रकार का भी बराबर हिस्सा है। यही कारण है कि, पुलिस और प्रशासन उदयगढ़ में चल रहे इस अवैध जुएं-सट्टे के क्लब पर हाथ डालने से कतराता है। अपने आपको वरिष्ठ कहने वाले इस सिखंडी पत्रकार ने अब तक जितने भी चेले अपने पत्रकारिता क्षेत्र में खड़े किए है वे सबके सब कहीं न कहीं जाकर अवैध धंधों, जमीन कब्जाने, शासकीय भूमियों को अपने नाम करवाने, भांजगड़ी और अधिकारियों को ब्लैकमेल करने जैसे अवैध कृत्यों में ही पल रहे है। मतलब पत्रकारिता न सिखाई पर अवैध धंधे सिखंडी पत्रकार ने अपने चेलों को जरूर सिखा दिए। बताया तो यह भी जाता है कि, जिस काले वाहन में यह सिखंडी पत्रकार कैमरा-आईडी लेकर चलता है वह भी रेत और नकली बॉयोडीजल माफिया गुल्लु की ही दी हुई देन है। यही कारण है कि, सिखंडी पत्रकार गुल्लु के भतीजे को साथ में रखकर पत्रकारिता की नहीं बल्कि अवैध धंधों की पाठशाला पढ़ा रहा है। गुल्लु के और भी कई अवैध कारनामें है, जिसे माही की गूंज समय-समय पर उजागर करता रहेगा।

इस तरह के राजनीतिक संरक्षण की बदोलत ही गुल्लु आलीराजपुर झाबुआ जिले में नए-नए गुल खिलाकर संरक्षकों की साख को बट्टा लगा रहा है।

गुल्लु की दबंगई, दादागिरी और रसूख को दर्शाती यह तस्वीर, जिसमें गुल्लु की कमर पर लटकी यह रिवाल्वर उसके केरेक्टर को दर्शा रही है।

गुल्लु के भाई रशीद उर्फ गुड्डू की कद्दावर कांग्रेसी नेताओं में है पैठ। कांतिलाल भूरिया के जन्मदिवस पर बधाई देने के इस अंदाज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुड्डू की भी पकड़ कांग्रेस में वैसी ही है जैसी गुल्लु की भाजपा में ।

ठेकेदार की लापरवाही से तीन युवा श्रमिको की मौके पर मौत

मनरेगा योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन घेरे में

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

पेटलावद तहसील के गांव तारखेडी समीप जुनापानी के बेरोजगार युवा राजस्थान मजदुरी करने गए थे, सॉफ-सॅफाई का करते समय मंगलवार को एक हादसा हुआ और 25 फीट गहरे सीवरेंज टेंक में गीर गए, इनमें सें तीन मजदुर की मौत हो गई। यह तीनो मजदुर पेटलावद तहसील के ग्राम जुनापानी के रहने वाले है। बैरोजगारी के चलते अपने जिले से अन्य शहरों, राज्य में मजदुरी करने के लिये जा रहे थे। जहां आये दिन हादसे होते रहते वे अपनी जान गवानी पडती है। राजस्थान के कोटा मे शहरी आधारभूत विकास योजना आर.यू.आई.डी.पी के बने सीवरेज टेंक में चार मजदूर सफाई कर रहे थे। सफाई कर रहे मजदूरो द्वारा कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहे थे, तभी बहार खडे मजदूरो ने अधिकारीयो को तुरंत सूचना दी बाद मे टेंक के अंदर देखा तो चारो मजदूरी अचेत अवस्था मे पडे मिले थे। दो मजदूरो को आक्सीजन लगाकर टेंक मे उतार कर चारो मतृ मजदूरा को टैंक से बाहर निकाला गया, जिनमे से तीन मजदूर कमल डामर (25), गलिया गुंडीया (24), क्रिरसिंह गुडिया (20), अहमद गंभीर रूप से घायल मिला। तीना मृतक परिवार सहित काम पर मजदूरी करने जाया करते थे। तीनो मजदूर की मौत का कारण प्रारंभीक कारण दम घुटने से सीवरेज टेंक कीं गहराई अधिक होने के कारण व टेंक के अन्दर अधिक किचड होने के कारण, मिथेन गैस जहरली बन गई थी तथा ऑक्सिजन नहीं होने के कारण मजदूरो की टेंक के अंदर ही मौत हो गई थी।

राजस्थान पुलिस मृतक कमल के भतीजे देवीलाल और उनके परिवार द्वारा अहमदाबाद को हेतवी कंट्रक्शन कम्पनी व ठेकेदार कुलदीपसिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मृतक का अंतिम संस्कार गृह गांव जुनापानी में बुधवार को किया गया।

विधायक वालसिंह मेड़ा सहित प्रशासन के अधिकारी पहुँचे अंतिम संस्कार में।

शोक में डूबा जूनापानी गाँव और मृतकों के परिजन।

असमय काल के ग्रास बने मजदूर ।

पर्याप्त मजदूरी कार्य नही इसलिए पलायन जारी, मनरेगा कागजों पर

अन्य राज्यों में जिले के पलायन कर मजदूरी के लिए गए ग्रामीण हादसों ओर दुर्घटना के शिकार होकर जान गवाते रहे है, साथ ही बहार के ठेकेदार कई बार मजदूरों का शोषण कर उनकी मजदूरी का भुगतान नही करते और बीचोलिये दलाल के भेंट चढ़ जाते हैं। मीडिया में मामले आते ही जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगते हैं कि, स्थानीय स्तर पर मनरेगा जैसी योजना होने के बाद भी जिले से बड़े स्तर पर पलायन जारी है। वर्तमान में विकास खंण्ड की बात की जाए तो मनरेगा योजना में न तो पर्याप्त कार्य चल रहे हैं और न ही पर्याप्त मजदूरी। विगत दिनों विकास खण्ड के सरपंचों द्वारा भी कार्य नही मिलने को लेकर सामूहिक आवेदन दिया था। मनरेगा के जो कार्य वर्तमान में चल रहे हैं उसमे भारी मशीनों का उपयोग की जा रहा है और केवल साठ-गांठ वाले ग्रामीणों के जाबकार्ड पर फर्जी मजदूरी के मस्टर जारी कर कार्य होना बताया जा रहे। मजदूरी के नाम प्रशासन कागजी हकीकत आंकड़े पेश कर अपनी पीठ थपथपा रहा है, इसके विपरीत जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है जिंसमे पलायन को लेकर प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

विधायक पहुंचे अंतिम संस्कार में

मृतक युवकों के गाँव जूनापानी में मातम परसा हुआ था और उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई गंभीर स्थिति निर्मित न हो इसलिए प्रशासन के अधिकारी और बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुँचा, जहा तीनो मृतकों के अंतिम संस्कार करवाया गया। भाजपा-कांग्रेस के कई नेता सहित क्षेत्र के विधायक वालसिंह मेड़ा भी पहुँचे ओर प्रशासन और सरकार से मृतक के परिवार को हर सम्भव मदत देने की मांग करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया।

मुख्यमंत्री ने वीसी के माध्यम से नव विवाहित जोड़ों को संबोधित करते हुए दिया आशीर्वाद

विकासखंड मेघनगर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के सामुहिक विवाह कार्यक्रम में 456 जोड़ों का विवाह संपन्न

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बुधवार को जिले के मेघनगर विकासखंड में 456 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न करवाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीसी के माध्यम से संबोधित कर नवविवाहित जोडो को आर्शीवाद दिया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सभी विवाहित जोडो को दिल से आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बेटियो के जीवन में सुख-समृद्धि आये, जीवन में खुशिया आए, भगवान हर खुशी इन्हें दे। भारत की संस्कृति में विवाह पवित्र आत्मा का बंधन है। जन्म-जन्म का साथ है। विवाह में दो परिवार जुडते है। मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सरकार ने बेटी व बहन की जिन्दगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए है, बेटियों के विवाह को बोझ नही रहने देगे, इसके पश्चात् मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी आयोजकों को धन्यवाद दिया, जिन्होने मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रत्येक जोडे को 49 हजार रूपए की राशि दी जाएगी।

सामूहिक विवाह समारोह में वर वधु को आशीर्वाद देने कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा, अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्री कलसिंह भाभर, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ललीता मुकेश मुणिया, उपाध्यक्ष श्रीमती सुशीला गोरसिंह भूरिया, श्री मुकेश मेहता, संगीता सोनी, सहायक संचालक श्री पंकज सावले सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग अधिकारी कर्मचारीगण सहित अन्य जनप्रतिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री द्वारा वार्ड क्रमांक 16 में हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई पट्टी पर अपने निर्धारित कार्यक्रम के पश्चात सीधा अपना काफिला लेकर झाबुआ नगरपालिका के क्रमांक वार्ड 16 में प्रेमलता भाभोर के घर गए। वहां पर प्रेमलता को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। साथ ही लच्छू बारिया, पुष्पेंद्र खाड़े, शालू खाडे, शांति डामोर, अन्नु, पायल डामोर, सुमित्रा वाखला, सुनीता वाखला, सुनीला वाखला, अनीता डामोर, संध्या भूरिया एवं पूजा डामोर को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी के साथ बैठकर चाय पी एवं कहा कि वे इस का इस एक हजार का सही उपयोग करे एवं सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सांसद गुमानसिंह डामोर, वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद पर्वत मकवाना एवं अन्य जनप्रतिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अन्तर्गत नियमित विमान सेवा आवेदन की अन्तिम तिथि 20 जून, 2023

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना अन्तर्गत नियमित विमान सेवा के वायुयान से तीर्थ यात्रा 21 मई से 19 जुलाई, 2023 तक आयोजित की जा रही है। जिसमें झाबुआ जिले में 19 जुलाई, 2023 (1 रात 2 दिन) झाबुआ से शिर्डी यात्रा प्रस्तावित है। आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि 20 जून, 2023 है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में हवाई यात्रा में पति-पत्नी, जो योजना की समस्त अर्हताओं की पूर्ति करते हो, यात्रा कर सकेंगे। शेष समस्त शर्तें पूर्ववत रहेगी।

स्टीविया, अकरकरा, तुलसी ,सर्पगंधा की फार्मिंग कर रहे किसान है खुश

माही की गूंज, धार।

देवारयन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन राज्य औषधि पादप बोर्ड के सलाहकार डॉ. पवन कुमार यादव एवं धार जिले के जिला आयुष अधिकारी डॉ रमेशचंद्र मुवेल एवं हॉर्टिकल्चर अधिकारी के पप्पू सिंह नरगिस धार जिले की तिरला में राहुल पटेल प्रेम सिंह परमार विमल पटेल कृषक तोल सिंह पटेल के साथ लगभग 250 किसान यह खेती कर रहे हैं, जो इस स्टीविया अकरकरा तुलसी सर्पगंधा की फार्मिंग कर रहे हैं। जिसका निरीक्षण बुधवार को किया गया, जिसमें वह किसान खेती कर कर बहुत खुश है। उन्होंने बताया कि विगत 10 वर्षों से यह औषधि फसल कर रहे हैं और अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके किसानों ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया।

पटवारी चल रहे डीके शिवकुमार की राह पर, कमलनाथ से नहीं बन रही बात

भोपाल।

मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एमपी में 150 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। कांग्रेस के अनुसार, कर्नाटक की तरह ही एमपी में भी वह जीत दर्ज कर सत्ता पर काबिज हो रही है। कांग्रेस की कर्नाटक के साथ एमपी की तुलना के अलावा भी एक समानता दिखाई दे रही है। वह है यहां धड़ों में बंटी कांग्रेस। यहां कांग्रेस का एक युवा तुर्क भी कर्नाटक के डीके शिवकुमार की राह पर चल दिया है। दरअसल, कर्नाटक में भी चुनाव होने से पहले यह माना जा रहा था कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैय्या के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है लेकिन, चुनाव आते-आते दोनों एक मंच पर दिखने लगे थे। हालांकि, अब चुनाव बाद दोनों नेताओं को लेकर फंसे पेंच को कांग्रेस ने सुलझा लिया है। अब नया पेंच नए चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में फंसता नजर आ रहा है।

कर्नाटक की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लिए दो धड़े मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दरअसल, कांग्रेस के युवा नेता जीतू पटवारी और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी पुष्टि इस बात से हुई कि हाल ही में कमलनाथ एमपी के बड़े कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे थे। वहीं राहुल गांधी के साथ एक बैठक होनी थी लेकिन, इस बैठक में जीतू पटवारी को नहीं बुलाया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि, जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच दूरी बढ़ गई हैं।

प्रदेश में इस वर्ष के नवंबर या दिसंबर महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के दो धड़ों में बंटना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि जीतू पटवारी और कमलनाथ के बीच ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए दोनों को साथ लाना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। हालांकि, कर्नाटक में भी कुछ इसी तरह के हालात थे, लेकिन कांग्रेस वहीं डीके शिवकुमार और सिद्धारमैय्या को एक मंच पर लाने में कामयाब रही थी और चुनाव में जीत दर्ज कर सरकार भी बनाई थी।

उड़ीसा के बाद म.प्र. में बेपटरी हुई रेल, पटरी से उतरे दो डिब्बे

जबलपुर।

उड़ीसा के बालासोर ट्रेन हादसे के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गईं। जबलपुर के शाहपुरा भिटोनी में एलपीजी रेक (गैस) ले जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। पश्चिम मध्य रेलवे के सीपीआरओ के मुताबिक, मालगाड़ी को अनलोडिंग करने के लिए रखे जाने के दौरान यह हादसा हुआ।

सीपीआरओ ने कहा, मंगलवार रात अनलोडिंग के लिए रखे जाने के दौरान एलपीजी रेक ले जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कारण ट्रेनों की मेनलाइन आवाजाही प्रभावित नहीं हुई। मेन लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही सामान्य रही। साइडिंग मालिक ने फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया है।

पहलवानों की खेल मंत्री के साथ चली लंबी बैठक, मिला आश्वासन

नई दिल्ली।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया की अगुवाई में शीर्ष पहलवानों की खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उनके आवास पर बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। अनुराग ठाकुर ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पहलवानों के साथ समझौता करने के सिलसिले में छह घंटे तक लंबी बातचीत की।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि 15 जून से पहले पुलिस जांच पूरी कर ली जाएगी। हमने अनुरोध किया है कि पहलवानों के खिलाफ सभी केस वापस लिए जाने चाहिए और उन्होंने इसके लिए हामी भर दी है। अगर 15 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपना विरोध जारी रखेंगे।

बजरंग पुनिया ने कहा, हमने कुछ मुद्दों पर चर्चा की थी। पुलिस की जांच 15 जून तक पूरी हो जानी चाहिए और मंत्री जी ने हमसे तब तक विरोध प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला पहलवानों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। हमने अनुरोध किया है कि पहलवानों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ली जानी चाहिए और वह इसके लिए सहमत हो गए हैं।

उधर पहलवानों के साथ छह घंटे तक लंबी बातचीत के बारे में जिक्र करते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पहलवानों से मेरी 6 घंटे लंबी चर्चा हुई। हमने पहलवानों को आश्वासन दिया है कि 15 जून तक जांच पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। 30 जून तक डब्ल्यूएफआई के चुनाव होंगे।

दो पक्षों में खूनी संघर्षः जमीन विवाद को लेकर चलाई गोली

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र बोरखेड़ा गांव जमीन विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी।गोलीकांड के बाद गांव में तनाव की स्थित बन गई। हालात को देखते हुए मोके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इलाज के बाद घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। जिसे रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया गया था।

बता दे कि, मंगलवार देर रात्रि में पिपलौदा थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम बोरखेड़ा में जमीन विवाद के चलते इकबाल नाम एक युवक ने लछु सेठ उर्फ लछु सिंधी को गोली मार दी। जिसके बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि, उपरवाडा के इकबाल का बोरखेड़ा में पोल्ट्री फार्म है, जिसके पास लच्छू सेठ की जमीन होने की बात सामने आ रही है। दोनों का पहले से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। गोली पसली में फसे होने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम रेफर किया।

श्री परमज्ञानी संत कबीर सत्संग समिति द्वारा 23 वाँ कबीर महोत्सव हुआ संपन्न

माही की गूंज, शाजापुर।

दुपाड़ा रोड, नेहरू स्मृति वन के पास कबीर आश्रम पर विशाल 23 वॉ आध्यात्मिक कबीर महोत्सव सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम कबीर साहब के मंदिर में माल्यार्पण कर शुरुआत की गई जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व केबिनेट मंत्री हुकुमसिंह कराड़ा, विशेष अतिथि पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब एवं महंत गोपाल दास साहेब, दिलीप सिंह बामनिया, कमल मालवीय, डॉ मनोज पंचोली, ओमप्रकाश मालवीय मैनेजर, नारायण सिंग मालवीय, राधेश्याम मालवीय, अनिल मालवीय, देवकरण गुर्जर आदि रहे।

कराड़ा ने कहा कि, कबीर साहेब किसी एक जाति या एक धर्म के ही नहीं थे अपितु सर्व समाज के मार्ग दर्शक थे। वह सभी के जीवन को सतमार्ग पर ले जाना चाहते थे। इसी कड़ी में पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब ने नशा मुक्ति से दूर रहने का सभी से आग्रह किया क्योकि नशा जीवन को नष्ट कर देता है। साथ ही सत्संग समिति की मांग पर माननीय विधायक जी द्वारा 3 लाख रुपये दुपाड़ा रोड़ से कबीर आश्रम तक रोड़ बनाने के लिए एवं 4 लाख रुपए टीन शेड के लिए दिए, कुल 7 लाख रुपए दिए गए। समिति के अध्यक्ष गोवर्धन लाल यादव, उपाध्यक्ष समंदर मकवाना, सचिव रमेश चंद्र सिसनोरिया, कोषाध्यक्ष दिनेश धानुक के साथ समिति सदस्य भागीरथ सोलंकी, मोहनलाल मालवीय, किशोर जी यादव, रतनलाल मेवाड़ा, कन्हैयालाल धानुक, नागूलाल फुलेरा, सुमन सिंग माँगरोलिया आदि एवं कबीर भजनो की प्रस्तुति लोक गायक पद्म श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया एवं प्रीतम मालवीय एवं अन्य साथियों द्वारा दी गई। कार्यक्रम में सैकड़ो की संख्या में कबीर साहब के अनुयायी मोजूद रहे कार्यक्रम का संचालन रामचन्द्र चोहान एवं माखनलाल धानुक ने किया। कार्यक्रम की जानकारी राजेश सिसनोरिया द्वारा दी गई।

22 किलो अवैध मादक पदार्थ के साथ आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, शामगढ़।

मंदसौर की शामगढ़ थाना पुलिस ने राजस्थान निवासी एक आरोपी के कब्जे से 22 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया है। जिसकी कीमत 44 हजार रुपए बताई गई। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ तस्करी का केस रजिस्टर्ड किया गया है। शामगढ़ थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात पुलिस मुखबिर से सूचना मिली थी कि, एक आरोपी अवैध मादक पदार्थ तस्करी कर राजस्थान जाने वाला है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड के निकट से आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली। आरोपी के कब्जे वाले बैग में 22 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया गया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भवरलाल पिता जय किशन बिश्नोई (22) निवासी ग्राम देवरी थाना बागोड़ा जिला जालौर राजस्थान का होना बताया है। आरोपी अवैध मादक पदार्थ किस व्यक्ति से लेकर आया था और कहां ले जा रहा था। जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपी के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ तस्करी की धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

एक दिन के धरने में ही लौट लगाने लग गया प्रोजेक्ट इंचार्ज संदीप

15 दिन में बंद नल चालू कर व्यवस्था सुधार की लिखित में ली जिम्मेदारी, नगर परिषद की भारी लापरवाही हुई उजागर

गूंज ने उठाया था ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्र में भी नल-जल मिशन योजना ध्वस्त होने का मुद्दा

माही की गूंज, पेटलावद।

विगत तीन माह से नगर परिषद और मुख्यमंत्री तक आवेदन देकर नगर में स्नेहिल वाटर सप्लायर कंपनी के द्वारा नगर भर में बिछाई गई नल-जल योजना की पाइप लाइन के घटिया कार्य और अनुबंध अनुसार सुविधा मोहया नही करवाने ओर अलग-अलग वार्डों में सैकड़ो नल कनेक्शन बन्द होने के चलते वार्ड क्रमांक 8 की महिला पार्षद ममता गुजराती शनिवार को धरने पर बैठकर कम्पनी द्वारा अधूरे कार्य को पूर्ण बताकर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर शासन से बकाया राशि लेने की कोशिश का विरोध दर्ज करवा रही थी। पार्षद ममता गुजराती का सीधा आरोप था कि, कम्पनी की भयंकर लापरवाही को अनदेखा कर उसे पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जा रहा है जिससे नगरवासियों को बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। महिला पार्षद ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को आवेदन देकर मांग कर चुकी थी और दस दिन के भीतर सुनवाई नही होने की दशा में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की बात कही थी। शनिवार को पार्षद अपने कहे मुताबिक मुख्य चौराहे पर धरने पर बैठ गई जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और स्नेहिल कंपनी के जबाबदारो सहित नगर परिषद सीएमओ को बुलवाया गया जहा कम्पनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज संदीप ने अनुविभागीय अधिकारी अनिल राठौर के सामने धरने पर बैठी पार्षद द्वारा बताई गई समस्या 15 दिन में सही करने का लिखित आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। पार्षद ममता गुजराती ने कहा है अगर समय पर कार्य नही किया गया तो वो वापस धरने पर बैठ जाएगी।

गूंज ने उठाया था मुद्दा

धरने के तुरंत बाद गूंज ने मामले की रिपोर्टिंग अपने यूट्यूब चैनल पर की थी, जिंसमे नगर में पाइप लाइन बिछाने वाली कम्पनी के कार्य पर बड़े सवाल खड़े हो रहे थे साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो में खराब हालत में पड़ी नल-जल मिशन योजना के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में ध्वस्त हुई योजना को लेकर सवाल खड़े किए गए जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया। मुद्दा मीडिया कवरेज के कारण मुख्यमंत्री तक नही पहुचे इसलिए भी कही न कही इस आंदोलन को दबाया गया।

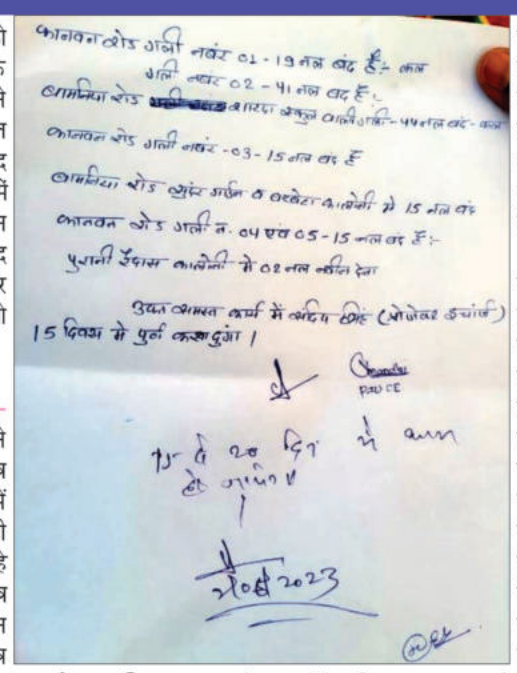

परिषद 24 घन्टे नल देने की योजना को लगा रही पलीता

पूरे मामले में नगर परिषद पेटलावद की घोर लापरवाही सामने आ रही है। योजना के मुताबिक आम जनता को इस योजना के माध्यम से 24 घन्टे पानी मिलना था जिसके लिए कनेक्शन के साथ-साथ मीटर भी लगाए गए थे, लेकिन कनेक्शन के साथ लगे अधिकांश मीटर या तो तोड़ दिए गए हैं या फिर चोरी कर लिए गए है।

मामले में प्रोजेक्ट इंचार्ज संदीप से जानकारी ली तो उनका कहना है कि, आम जनता को 24 घंटे पानी की सुविधा देने है जो अनुबंध में है, उसी अनुसार मीटर हर कनेक्शन के साथ लगाए गए थे, लेकिन ज्यादा तर मीटर लोगो ने या तो तोड़ दिए या चोरी होने की बात कह दी, जिसकी जानकारी हमारे द्वारा वरिष्ठ कार्यालय सहित नगर परिषद को लिखित में दे दी थी। लेकिन स्वयं नगर परिषद 24 घन्टे की जल सप्लाई सुविधा न चाह कर दो दिन में एक दिन वो भी आधे घंटे पानी सप्लाई करने का बोल रही है। प्रोजेक्ट इंचार्ज ने बताया कि, पानी का दुरुपयोग न हो और व्यर्थ न जाये इसके लिए मीटर ओर बिल की व्यवस्था की गई थी जिसके लिए सारे सामग्री और बिल बनाने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग तक दे दी गई है, लेकिन मीटर के माध्यम से कोई पानी नही चाहता क्योकि हर कोई सीधे मोटर से पानी लेना चाहता है और मोटर से पानी लेने से बिल भी अधिक बनता इसलिए लोगो ने मीटर निकाल दिए और नगर परिषद ने कोई कार्यवाही नही की। खराब ओर बन्द पड़े कनेक्शनो की शिकायत मिलने पर हम सुधार करने को तैयार है।

नगर परिषद को हैंड ओवर करने की बात गलत

एक ओर कहा जा रहा है कि, योजना के पूर्णता प्रमाण पत्र मिलने के बाद योजना नगर परिषद को संचालित करने के लिए सोप दी जाएगी। वही प्रोजेक्ट इंचार्ज का कहना है कि, दस साल का कम्पनी का करार है और दस साल तक इस योजना के संचालन का मेंटेनेंस कम्पनी को ही करना है। आरोप-प्रत्यारोप के बीच मामला पेचीदा हो गया हैं, आखिर इस योजना का भट्ठा बिठाने वाला कौंन है स्वयं नगर परिषद जो लोगो को 24 घंटे जल प्रदाय से वंचित कर रही है या ठेकेदार जो योजना को सरकारी अनुबंध के अनुसार नही पहुचा पा रहा है या आम जनता जो पानी के बिल से डर कर बिना मीटर के पानी चाह रही है।

जिला पंचायत सीईओ ने दिये मोहनकोट पंचायत के जांच के आदेश

जनसुनवाई में ग्रामीणों ने की थी भ्रष्टचार की शिकायत, कई पंचायतों का भ्रष्टाचार फाइलों में दबा, क्या ये भी भ्रष्टचार फाइलों में दबेगा या निष्पक्ष होगी जांच...?

माही की गूंज, पेटलावद।

लगभग 15 दिन पूर्व विकास खंड की ग्राम पंचायत मोहनकोट के ग्रामीणों ने झाबुआ कलेक्टर कार्यालय पहुचकर ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे कार्यो में भारी भ्रष्टचार और बिना कार्य किये फर्जी बिलो के भुगतान की शिकायत जनसुनवाई में दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद ग्रामीणों को किसी तरह की कार्यवाही या जांच की कोई जानकारी नही दी गई। मंगलवार को पुनः ग्रामीण झाबुआ पहुचे जहा जिला सीओ ने पत्र बताते कहा कि, मामले की जांच के आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद को दे दिए गए हैं। ज्ञात है इससे पूर्व भी कई पंचायतों के भ्रष्टचार की शिकायत जिले से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई, जिसकी जांच के आदेश हुए लेकिन उनकी जांच आज भी फाइलों में दबी हुई है। ताज़ा मामला बोडायता पंचायत का भी आया था जहां निर्माण कार्य तक जमीन स्तर से गायब होने की शिकायत हुई थी उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है। एक ओर मुख्यमंत्री भ्रष्टचार जड़ से खत्म करने के दावे भरते है और दूसरे ओर उनके अधिकारी खुले भ्रष्टचार में शामिल होते हैं। शिकायत के बाद जांच के नाम पर शिकायतकर्ताओं को गुमराह कर शिकायत दबा दी जाती है। मोहनकोट पंचायत मामले में शिकायतकर्ताओ का साफ कहना है कि, अगर शिकायत पर सही जांच और कार्यवाही नही हुई तो विधानसभा चुनाव में परिणाम भुगतने के लिए सत्तापक्षीय नेता तैयार रहे जो इस मामले में कोई सुनवाई नही कर रहे हैं।

शराब ठेकेदार की बल्ले-बल्ले

कुंभकरण की नींद में सोई आबकारी और पुलिस, कार्रवाई के नाम पर जीरो

माही की गूंज, बनी।

जिला कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने आबकारी विभाग को सतत् कार्यवाही करने के निर्देश दे रखे है। मगर आबकारी विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश को हवा में उड़ा दिया जाता है। इसका ताजा उदाहरण रायपुरिया शराब ठेकेदार द्वारा चार पहिया वाहन से गांव-गांव शराब डालने से स्पष्ट प्रतीत होता है और आबकारी विभाग अपनी खानापूर्ति करने के लिए होटल, ढाबों, का चक्कर लगाकर इतिश्री करने में लगी है। रायपुरिया शराब ठेकेदार द्वारा गांव-गांव शराब डालना यह सिद्ध करता है कि, पुलिस और आबकारी अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने में कितनी कर्तव्यनिष्ठ है। वैसे तो पूरे जिले में पुलिस कप्तान अगम जैन के निर्देश में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान बड़ा जोर शोर से चलाया जा रहा है और पुलिस भी कप्तान साहब के सामने अपना कद ऊंचा करने के लिए इक्का-दुक्का अवैध रूप से शराब बेचने वाले को पकड़ कर केस दर्ज कर लेती है और इति श्री कर देती है। मगर रायपुरिया क्षेत्र के हर गांव में शराब ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से शराब डाली जा रही हे, शुरुआत में शराब ठेकेदार द्वारा एक फोर व्हीलर गाड़ी से शराब की सप्लाई गांव-गांव की जाती थी, मगर वर्तमान स्थिति में रायपुरिया शराब ठेकेदार द्वारा तीन, चार पहिया वाहनों से गांव खेड़े तक शराब डाली जा रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि, पुलिस और आबकारी दोनों ही शराब ठेकेदार के इशारे पर काम करती है या यूं कहें कि, दोनों विभाग कुंभकरण की नींद मैं सोए हुए हैं।

20 साल बाद भी सिग्नल पट्टी रोड

माही की गूंज, रायपुरिया/बनी

बीते 20 वर्ष पूर्व रायपुरिया से जूनापानी रोड सिग्नल पट्टी का डामरीकरण ठेकेदार मनोहर लाल भंडारी झाबुआ के द्वारा किया गया था। मगर 20 वर्ष बीतने के बाद भी रायपुरिया से जूनापानी रोड का डामरीकरण सिग्नल पट्टी के रूप में फिर से कर दिया गया। इस रोड की ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग और ना ही किसी रूलिंग सरकार के नेताओं ने ध्यान दिया। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि, रायपुरिया से लेकर बेकलदा, हमीरगढ़, माही तक दो लाइन का निर्माण हो चुका है और इन दो लेन निर्माण रोड पर इतना ट्राफिक भी नहीं है जबकि रायपुरिया से जूनापानी तक के रोड पर विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी का मंदिर है जहां मंगलवार के दिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और अत्यधिक ट्राफिक होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस मार्ग पर पलक झपकते सैकड़ों वाहन गुजर जाते हैं, ट्राफिक की अधिकता के चलते बनी के समीप रोड निर्माण के समय आमने-सामने दो मोटरसाइकिल की टक्कर मैं एक मोटरसाइकिल सवार जोकी सरदारपुर का निवासी था अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इस मार्ग पर वर्तमान सांसद गुमानसिंह डामर का गृह निवास उमरकोट है मगर सांसद ने भी इस रोड की सुध नहीं ली। अगर अपने पद का थोड़ा सा प्रभाव बताते तो यह रोड डबल पट्टी बन जाता तो कितने ही लोग दुर्घटना का शिकार होने से बच जाते।

रायपुरिया से जूनापानी रोड इंदौर-अहमदाबाद फोर लेन से मिलता है जिस वजह से यात्री बसे और निजी वाहन से लोग इंदौर का सफर तय करते हैं। रायपुरिया से बनी की ओर सफर करते समय रायपुरिया और बनी के बीच खतरनाक मोड़ है इस मोड़ पर कई वाहन सवार अपनी जान गवा चुके है। मगर वर्तमान ठेकेदार द्वारा खतरनाक मोड़ के दोनों और स्पीड ब्रेकर का निर्माण नहीं किया, उसकी वजह यह है कि, इस खतरनाक मोड़ की ओर पीडब्ल्यूडी विभाग ने ध्यान नहीं दिया या फिर इसे ठेकेदार की लापरवाही कहें। वर्तमान ठेकेदार द्वारा रोड की दोनों और साइट पटिया भरने का काम धीमी गति से चलने के कारण कई वाहन सवार क्रॉसिंग करते वक्त दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।

निःसंतान बुजुर्ग दंपति ने किया शादी समारोह का आयोजन

शादी के 55 साल बाद गंगाजल, सुंदरकांड जैसे धार्मिक आयोजन कर मनाई वर्षगांठ

माही की गूंज, पेटलावद।

नवयुवक-युवती को विवाह बंधन में बंध जाने की परंपरा तो आपने देखी और सुनी होगी। परंतु किसी बुजुर्ग दंपति के दोबारा विवाह बंधन में बंधने और शादी समारोह आयोजित करने की बात आपको आश्चर्य मे डाल देगी। ठीक 55 साल बाद दुल्हन भी वही दूल्हा भी वही, लेकिन बदला तो केवल समारोह का अंदाज। आज के जमाने के अनुसार स्टेज प्रोग्राम सहित विभिन्न आयोजन कर शादी की सालगिरह पर शादी समारोह का आयोजन कर दिया।

हम बात कर रहे है पेटलावद निवासी बाबू दास बैरागी व उनकी धर्मपत्नी रतनबाई बैरागी की, जिन्होंने वैवाहिक जीवन के 55 वर्ष मे दोबारा शादी समारोह आयोजित किया। वही धार्मिक कार्यक्रमो का आयोजन कर परिवार रिश्तेदार को भोज भी करवाया। आम तौर पर शादी के समय जो कार्यक्रम रखे जाते हैं उनका निर्वहन भी बखूबी किया गया। दरअसल बाबू दास और रतन बाई दोनो को कोई संतान नही है। ऐसे मे जीवन के लंबे समय की खुशियों को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। वैवाहिक जीवन के 55 वर्ष के लंबे समय गुजरने के बाद रिश्तेदारो के बीच फिर से पुराने जीवन की याद ताजा की। उनके इस आयोजन के साथ सुंदरकांड, गंगाजल, सत्यानारायण कथा समेत धार्मिक आयोजन भी किए।

बाबूदास बैरागी ने बताया कि, वैवाहिक जीवन को 55 वर्ष बीते हैं, हम सोचते थे हमारे बच्चो का विवाह हम करते परंतु हमारी कोई संतान नहीं है। ऐसे मे रिश्तेदारो और परिवार के बीच यह आयोजन किया।

संत के साथ अमर्यादित व्यवहार से जैन धर्मावलंबियों में आक्रोश

माही की गूंज, पेटलावद।

जैन संत के साथ कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने व अमर्यादित व्यवहार किये जाने की घटना से जैन धर्मावलंबियों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। पेटलावद में समग्र जैन समाज, हिन्दू जागरण मंच, अरिहंत युवा वाहिनी ने संयुक्त रूप मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौपा। रविवार को सभी प्रतिनिधि दोपहर में सिटी केमिस्ट से एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुचे, यहा पर समग्र जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था महावीर समिति के अध्यक्ष संजय चाणोदिया, हिन्दू जागरण मंच के प्रकाश प्रजापत ने भी सम्बोधित किया। यहा पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार मुक़ामसिंह निगवाल को सौपा गया। ज्ञापन का वाचन विनोद भंडारी ने किया। संचालन जितेंद्र कटकानी ने किया। आभार पंकज जे पटवा ने माना। अभा जैन पत्रकार संघ ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभा जैन पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप डाकोलिया, सरंक्षक हिम्मत मेहता, ऋतुराज बुडावनवाला, संस्थापक अध्यक्ष संजय लोढ़ा ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को एक पत्र लिखकर बताया कि, प्रदेश ही नही देश भर में चातुर्मास काल के अतिरिक्त सभी सम्प्रदाय के जैन सन्त उग्र विहार करते हुए धर्म प्रभावना करते है, अनेकों बार जैन संतो को बेहद विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। थांदला में घटित घटना इस अहिंसक समाज के लिए पीड़ादायक है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज पटवा, वरिष्ठ पत्रकार अनिल मुथा, राहुल मुथा, पियूष पटवा, सन्दीप बरबेटा, विपुल लोढ़ा ने बताया कि, प्रशासन तंत्र साधु संतों के आगमन, विहार तथा धर्म स्थल आदि पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करे जिससे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नही हो तथा थांदला की घटना में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये।

भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल, विधायक भूरिया ने दिलाई सदस्यता

माही की गूंज थांदला।

थांदला विकासखंड में आने वाली ग्राम पंचायत खोखर खादन में मंगलवार को बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा। थांदला विधानसभा क्षेत्र मे बीजेपी के 100 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। थांदला विधायक वीरसिंह भूरिया ने कांग्रेस का गमछा गले में डालकर सदस्यता दिलवाई। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व सरपंच वाहडिया मईडा, बीजेपी के युवा नेता एवं पंच अनिल डामोर, देवचंद्र अमलियार, रमेश गुडिया, नरु डामोर, कैलाश डामोर, पपु मईडा ,मोगेश गुडीया, सबु समसु गुंडीया, पकु गुडिया, बेनजु गुडिया, मुकेश गुडिया, दिनेश गुडिया एवं समस्त 100 से अधिक ग्राम पंचायत खोखर खानदान एवं ग्राम बोरवा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल हुए।

बीजेपी के पूर्व सरपंच वाहडिया मईडा का कहना है कि, बीजेपी में हमारी कोई सुनवाई नहीं है बीजेपी सरकार से समस्त जनता परेशान है, जनता की परेशानी देखते हुए मैं बीजेपी को छोड़ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा हूं, आज से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए विधायक वीरसिंह भूरिया के लिए कार्य करूंगा, कांग्रेस सरकार ने ही गरीबों को कर्ज माफ किया इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी अच्छी लगी। कांग्रेस सरकार में जनता खुश थी, आज बीजेपी सरकार में महंगाई आसमान छू रही एवं युवा बेरोजगार हो गए हैं ऐसी भ्रष्टाचारी बीजेपी पार्टी मे मैं नहीं रह सकता।

अनिल डामोर ने बताया कि, बीजेपी सरकार में बैठे नेताओं को बार-बार मेरे द्वारा अवगत कराने के बाद भी मेरे फलिया में पानी की समस्या होने से मैं बहुत परेशान था, बीजेपी सरकार में बीजेपी के कार्यकर्ता को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा ऐसी पार्टी मैं नहीं रह सकता मैं अब कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। इस अवसर पर थाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीर सिंह भूरिया ने कांग्रेस में सम्मिलित हुए सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की नीति से अवगत करवाकर कांग्रेस की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का भी आह्वान किया साथ ही कमलनाथ द्वारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर जो वचन दिया गया है उसे भी मतदाता तक पहुंचने को कहा।

इस कार्यक्रम में उपस्थित भूरिया, कांग्रेस पार्टी के जिला संगठन मंत्री जसवंत सिंह भाबर, सरपंच सतरु खोखर, सरपंच रुसमाल मईडा, उपसरपंच अनु भूरिया, पूर्व सरपंच रालु वसुनिया, विलयम मावी एवं समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

संपादकीय

भ्रष्टाचार के दरिया में कैसे टिकेगा निर्माण

यह भ्रष्टाचार में डूबी व्यवस्था का ज्वलंत उदाहरण ही है कि, बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल जैसे संवेदनशील निर्माण में इतनी धांधली हुई कि एक दशक से बन रहा हजारों करोड़ का पुल बनने से पहले दो बार टूट गया। एक वर्ष पहले पुल के हिस्से के ध्वस्त होने के बाद भी न तो किसी की जवाबदेही तय की गई और न ही किसी को दंड मिला। विडंबना यह कि, गत रविवार को एक हजार 710 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले पुल का एक बड़ा हिस्सा फिर ढह गया। यदि यह हादसा पुल पर जारी यातायात के बीच होता तो जनधन की हानि का अंदाजा लगाया जा सकता है। उस पर तुर्रा यह है कि, बिहार सरकार में शामिल दलों की तमाम दलीलें भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की हो रही हैं। बेतुकी दलील दी जा रही है कि, पुल के डिजाइन में खामी के कारण पुल के एक हिस्से को गिराया गया। इससे पहले सार्वजनिक जीवन में किसी ने इस तरह की दलील नहीं सुनी, यह सिर्फ हादसे के बाद लीपापोती की कवायद है। निश्चय ही घटना विचलित करती है कि हजारों लोगों के जीवन से जुड़े सार्वजनिक निर्माण में किस हद तक हेराफेरी और कमीशन बाजी चलती है कि निर्माण पूरा होने से ही पहले ही वह भरभरा कर गिर जाता है। यह भी कि राजनेताओं और ठेकेदारों के लिए आम आदमी की जिंदगी की कीमत क्या है। बीते वर्ष गुजरात में हुए एक पुल हादसे में आपराधिक लापरवाही से बड़ी संख्या में लोगों के डूबकर मरने की घटना से लगता है हमने कोई सबक नहीं लिया। देश में ऐसी कोई स्वतंत्र व अधिकार संपन्न नियामक संस्था नजर नहीं आती तो सार्वजनिक निर्माण में आपराधिक लापरवाही को पकड़कर दोषियों को दंडित करे। घटना निर्माण कार्य से जुड़े जवाबदेह लोगों की नैतिकता पर भी सवाल खड़ा करती है। यह मामला ऐसे समय में प्रकाश में आया है जबकि देश भयानक लापरवाही से हुई ओडिशा रेल दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत के दुख से उबर नहीं पाया है।

नि:संदेह, भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के एक हिस्से के धंसने की घटना संरचनात्मक निर्माण की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लगाती है। सवाल यह भी है कि वर्ष 2014 में बनना शुरू हुआ यह पुल 2023 तक भी क्यों नहीं बन पाया है। जिस पुल को लेकर दावे किये जा रहे थे कि इससे यात्रा का समय कम होगा और संपर्क मार्ग आसान होगा, एक दशक होने पर भी उस पुल का निर्माण न तो पूरा हुआ बल्कि जो बना भी है वह भरभरा कर गिर रहा है। पुल निर्माण की सीमा का चार बार बढ़ाया जाना बताता है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के यह संभव नहीं हो सकता। तभी बिहार सरकार में शामिल राजनीतिक दल कुतर्कों के जरिये लीपापोती में लगे हैं। निस्संदेह, बार-बार निर्माण की समय अवधि बढ़ाए जाने से उसकी लागत भी बढ़ जाती है और यह पैसा जनता से उगाहे कर के द्वारा ही चुकाया जाता है। जहां राज्य सरकार मामले में जांच के आदेश दे रही है वहीं सरकार में शामिल एक दल के नेता कह रहे हैं कि इस पुल के डिजाइन में खामी थी और इसे दुरुस्त करने में आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ इंजीनियरों की मदद ली गई थी। दलील दी गई कि पुल के डिजाइन में खामी के चलते इसके एक हिस्से को गिराया गया। सरकार के बाएं-दाएं हाथ की अलग-अलग टिप्पणी संदेह को और गहरा करती है। नि:संदेह, इससे प्रश्न पैदा होता है कि जब डिजाइन में खामी के चलते पुल के एक हिस्से को गिराया गया तो मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश क्यों दिये? जाहिर है मामले में लीपापोती की जा रही है। निस्संदेह यह दुखद स्थिति है कि सच्चाई पर पर्दा डालकर जनहितों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल यह भी है कि पुल बनने के बाद यदि ऐसे हादसे होते रहे तो जान-माल की क्षति के लिये कौन जिम्मेदार होगा...? या तब भी कोई नया बहाना गढ़कर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया जायेगा। कायदे से तो सारे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाकर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए।

किसानों को भी मिले कार्पोरेट जैसी उदार मदद

विदेश यात्रा के दौरान क्रेडिट कार्ड के जरिये भुगतान पर 20 प्रतिशत कर लगाने पर माहौल गर्माने के बाद सोशल मीडिया पर रोचक बहस छिड़ गई। एक जाने-माने और बड़े कारोबारी ने एक पोस्टर साझा किया, जिसकी इबारत थी, 'मैं एक करदाता हूं, मेरा कर राष्ट्र के लिए है, न कि मुफ्त की रेवड़ियां लुटाने को।' इस ट्वीट ने खासी प्रतिक्रिया अर्जित की।

सरकार ने अपने रुख में लचीलापन दिखाते हुए संशोधन किया कि 20 प्रतिशत कर तभी लगेगा जब विदेश में क्रेडिट कार्ड आधारित भुगतान की रकम 7 लाख से ज्यादा बने। इस पर भी ट्वीटर पर रोचक एवं अर्थपूर्ण प्रतिक्रियाएं आईं। एक ट्वीटर उपभोक्ता ने कहा- 'जब सिपाही सीमा पर खड़े हैं, तो अमीर आदमी क्यों नहीं क्रेडिट कार्ड से किए भुगतान पर 20-प्रतिशत टैक्स भर सकता।' यह ऐसा जुमला है जो नोटबंदी समर्थकों द्वारा गढ़े गए 'तर्कों' से प्रेरित लगता है।

अमीर वर्ग ने सावधानीपूर्वक और निरंतर प्रचार से आभास गढ़ा है मानो देश का विकास केवल उनके यानी कॉर्पोरेट्स द्वारा चुकाए करों पर निर्भर है। यह बात सही है कि जो लोग परोक्ष कर भरते हैं उनकी चिंता इस बात पर जायज है कि उनके कराधान का पैसा कहां जा रहा है। लेकिन यह आभास देना कि सिर्फ अमीर ही कर भरता है, एकदम गलत है। जीएसटी के आने के बाद से, एक गरीब आदमी अगर हवाई चप्पल जैसी वस्तु खरीदता है तो भी टैक्स भरता है। आम नागिरक अन्य आवश्यक वस्तुओं पर भी कर चुकाता है, जिसमें थैलीबंद दूध एवं पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद भी शामिल हैं।

फैलाई गई कहानी कि केवल कॉर्पोरेट्स ही कर भरते हैं, इसको बदलना होगा। जैसा कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में निचले तबके वाली 50 प्रतिशत जनसंख्या कुल जीएसटी उगाही में दो-तिहाई है, जबकि चोटी का 10 प्रतिशत वर्ग केवल 3-4 फीसदी। यहां, चोटी के 10 फीसदी अमीरों में वे हैं, जिनकी कमाई 25000 रुपये महीना या इससे अधिक है।

बात पुनः ट्वीटर पर चली बहस की करें तो अपने उत्तर में मैंने ट्वीट किया- 'हां, मेरे कर का पैसा कॉर्पोरेट्स को मुफ्त की खैरात देने में इस्तेमाल के लिए नहीं है।' इस ट्वीट पर काफी संख्या में लोगों ने देखा, अभी तक यह संख्या 301000 पार हो चुकी है। यह साफ दर्शाता है कि समाज के काफी बड़े तबके को अहसास है कि कैसे कॉर्पोरेट्स को मुफ्त की खैरात मिल रही है और वह भी तथाकथित तरक्की की आड़ में। यहां मुख्य बात यह है कि हम वाकई नहीं चाहते कि हमारा धन कॉर्पोरेट्स को मुफ्त की रेवड़ियों की तरह बंटे।

पहले यह जानने की कोशिश करें कि लोगबाग कॉर्पोरेट्स को मुफ्त की खैरात बांटने पर क्यों खफा हैं। भारत में, अन्य मुल्कों की भांति, कॉर्पोरेट्स को फायदा न केवल लंबे समय की कर-वसूली में माफी देकर बल्कि घटी दरों का कॉर्पोरेट्स टैक्स और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देकर भी पहुंचाया जाता है और उनकी मदद अन्य तरीकों से, जैसे कि सस्ती दर पर जमीन, सस्ती बिजली और सब्सिडी वाला बैंक ऋण इत्यादि देकर भी की जाती है। जहां उद्योग जगत सोचता है कि यह प्रोत्साहन तरक्की के लिए है, जबकि कुछ समय पहले हुए एक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में माना था कि जिसे उद्योगों को बढ़ावा देने वाला प्रोत्साहन कहा जाता है, वह भी एक सब्सिडी है।

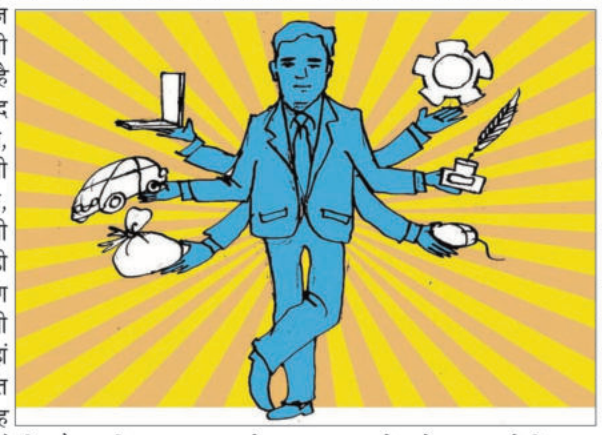

राष्ट्र के खजाने को खाली करने के अलावा मुफ्तखोर देश के प्राकृतिक स्रोतों का भी दोहन करते हैं। इसने वह आय असमानता भी पैदा कर डाली है, जो हर साल बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के अध्ययन के मुताबिक, हर साल उद्योग जगत को 7.3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की प्राकृतिक संपदा के दोहन की छूट दी जाती है। इतने विशाल स्तर की सब्सिडी हटा दी जाए तो कॉर्पोरेट्स का मुनाफा धराशायी हो जाएगा। इसलिए अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब और गरीब।

अनुमान बताते हैं कि दुनियाभर में चोटी के अमीर, जो कि सकल जनसंख्या का 0.01 प्रतिशत हैं, उनके हाथ में इतनी धन-संपदा का नियंत्रण है जो निचले पायदान पर बैठी 90 फीसदी जनसंख्या के बराबर है।

ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों केवल अमीरों को ही बैंकों से ऋण माफी के अलावा घटी दर पर कर भरने का लाभ मिलता है? उदाहरणार्थ, भारत में, कोविड महामारी से पहले, 2019 में कॉर्पोरेट जगत को हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपये की कर-छूट दिये जाने की घोषणा की गई। इतनी विशाल कर-छूट ऐसे समय पर दी गई जब अधिकांश अर्थशास्त्री राष्ट्रीय धन को ग्रामीण क्षेत्र में वस्तु-मांग बढ़ाने के लिए उपयोग करने की सलाह दे रहे थे। कॉर्पोरेट्स को मिली यह सौगात 1.8 लाख करोड़ रुपये के उस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के अलावा है, जो वर्ष 2009 में वैश्विक महामंदी के बाद भारत सरकार ने उद्योग जगत को दिया था। इसका मतलब है कि इन सालों में 20 लाख करोड़ रुपए पहले ही अमीरों को जा चुके हैं। अगर कहीं यह पैसा केवल कृषि क्षेत्र में निवेश कर दिया जाता तो खेती संबंधी संत्रास इतिहास की बात हो जाता।

दूसरी ओर, जब भी सरकार प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति तिमाही 2000 रुपये जारी करती है तो इसका प्रचार बड़े जोर-शोर से किया जाता है, इसके बरक्स कॉर्पोरेट जगत को हर साल 1.45 लाख करोड़ रुपये की कर-छूट का जिक्र तक नहीं होता।

वित्तीय वर्ष 2021 की समाप्ति तक भारतीय बैंकों ने कॉर्पोरेट जगत के अनचुके ऋण की 11.68 लाख करोड़ रुपये की विशाल राशि बट्टे खाते में डाल दी है। रोचक कि, मार्च, 2022 तक, इरादतन ऋण अदायगी न करने वालों में चोटी के 50 कर्जदारों की तरफ बैंकों का 92,570 करोड़ रुपये बकाया था। ये वह लोग हैं जो कर्ज वापस करने की स्थिति में हैं, लेकिन करना नहीं चाहते।

देविंदर शर्मा

इसी प्रकार, सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 क्षेत्रों में 1.97 लाख करोड़ रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वास्तव में, यह सब्सिडी पहले संत्रास भुगत रही कृषि को दिए जाने की जरूरत थी।

विडंबना है कि व्यापार जगत के कुछ अग्रणी लोग मानते हैं कि बैंकों द्वारा माफ किया धन उनके मुनाफे से है, इसलिए इसका संबंध कराधान से मिलने वाले पैसे से नहीं है। लेकिन शायद वे यह मानना नहीं चाहते कि बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए पैसे की वसूली सरकार अन्य ढंग से करती है, जिसका मतलब कि यह ऋण-माफी दरअसल आम कर-दाता के पैसे से होती है। सवाल यह भी कि क्यों भारत में केवल कॉर्पोरेट्स को ही ऋण-माफी की सुविधा है जबकि छोटा-सा कर्ज न चुका सकने की एवज में किसी किसान को जेल तक जाना पड़ जाता है? क्यों इरादतन ऋण-चोरों से बड़ी नरमी से बर्ताव जबकि कर्ज देने में चूके किसान को जेल की सजा?

यह देखना दर्दनाक है कि कैसे किसान मंडी में वाजिब दाम न लगने के कारण अपना आलू, प्याज, टमाटर, गोभी आदि उत्पाद सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं। खेती में संत्रास पिछले काफी वक्त से कायम है। खेत-मजूरी भी काफी सालों से एक जगह पर अटकी है। सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता यह वह अनियोजित क्षेत्र है जिसे फौरी मदद की जरूरत है। यदि कृषि फले-फूलेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनेक पहलुओं पर इसका सकारात्मक असर होगा लिहाजा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था भी ऊपर चढ़ेगी। यही वह क्षेत्र है मेरे द्वारा चुकाए टैक्स का पैसा जाना चाहिए।

मानवीय क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहे है महासागर

जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, जलवायु परिवर्तन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग इत्यादि विषयों पर प्रकाश डालने तथा महासागरों की वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में दुनिया में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 8 जून को 'विश्व महासागर दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस महासागरों को सम्मान देने, उनका महत्व जानने तथा उनके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अवसर प्रदान करता है। मानव जीवन में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका और इनके संरक्षण के लिए अनिवार्य प्रयासों के संबंध में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए ही इस दिवस का आयोजन किया जाता है। दरअसल समुद्रों का हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन बढ़ते मानवीय क्रियाकलापों के कारण दुनियाभर के महासागर बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं। इसीलिए विश्व महासागर दिवस के आयोजन के जरिये समुद्रों की साफ-सफाई के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के साथ लोगों को उनके रोजमर्रा के जीवन में महासागरों की प्रमुख भूमिका का स्मरण कराया जाता है। दरअसल भोजन और दवाओं के प्रमुख स्रोत तथा जीवमंडल का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं महासागर, इसीलिए इनका संरक्षण बेहद जरूरी है। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित बहुचर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के मुताबिक महासागरों का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बड़ा महत्व है और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ इन्हीं महासागरों से ही माना जाता है। ऐसा माना गया है कि पहली बार महासागरीय जल में ही जीवन का अंकुर फूटा था लेकिन आज यही महासागर प्रदूषण के बोझ से कराह रहे हैं। दरअसल दुनिया में विकास की रफ्तार तेज होने के साथ महासागरों के दूषित होने की गति भी उसी तेजी से बढ़ती गई है।

रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में हुए 'पृथ्वी ग्रह' नामक फोरम में प्रतिवर्ष 'विश्व महासागर दिवस' मनाने का निर्णय लिया गया था। तब कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डवलपमेंट तथा ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' में इसकी अवधारणा का प्रस्ताव रखा गया था। इस अवधारणा का मूल उद्देश्य लोगों को महासागरों पर मानवीय क्रियाकलापों के प्रभावों को सूचित करना, महासागर के लिए नागरिकों का एक विश्वव्यापी आन्दोलन विकसित करना तथा विश्वभर के महासागरों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर वैश्विक आबादी को जुटाना व एकजुट करना है। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस अवलोकन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई, जिसके बाद यह दिवस 'द ओशन प्रोजेक्ट' तथा 'वर्ल्ड ओशन नेटवर्क' के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाने लगा।

वायु और जल ही पृथ्वी पर जीवन के आधार हैं और हमारी पृथ्वी का करीब दो तिहाई हिस्सा महासागरों से घिरा है, जिनमें पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल का करीब 97 प्रतिशत जल समाया हुआ है। हालांकि पृथ्वी का इतना बड़ा हिस्सा जल से घिरा होने के बावजूद दुनियाभर में शुद्ध पानी की मात्रा बेहद कम है। समुद्रों से घिरे होने के कारण ही पृथ्वी को 'वाटर प्लैनेट' भी कहा जाता है लेकिन अब इसी वाटर प्लैनेट का अस्तित्व खतरे में है। महासागर पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं और पृथ्वी पर जीवन का प्रतीक हैं। अनादिकाल से महासागर जीवन के विविध रूपों को संजोए हुए हैं, जिनमें अति सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय व्हेल तक अनेक प्रकार के जीव-जंतु और वनस्पतियां पनपती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्रों में जीवों की करीब दस लाख प्रजातियां मौजूद हैं, जिनका प्राकृतिक आवास हैं महासागर। असीम जैव विविधता के प्रतीक महासागर पृथ्वी के फेफड़ों की भांति हैं, इन्हीं से पूरी दुनिया को अधिकांश ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम सांस लेते हैं। इसके अलावा मानव द्वारा उत्पादित तीस फीसदी से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी के यही फेफड़े ग्रहण करते हैं। 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक में बताया गया है कि महासागर ऑक्सीजन प्रदान करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण के अलावा हमारी जलवायु को भी स्थिर रखने में भी मदद करते हैं, बड़ी मात्रा में हवा तथा भोजन प्रदान करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने में मददगार होते हैं। मौसम में आने वाले बदलाव तथा जलवायु परिवर्तन की जानकारी प्रदान करने में भी महासागरों की अहम भूमिका होती है। तटीय इलाकों में रहने वाली दुनिया की करीब तीस फीसदी आबादी का तो जनजीवन पूरी तरह से महासागरों पर ही निर्भर है। विशाल महासागरों से पैट्रोलियम के साथ-साथ अनेक अन्य संसाधन भी प्राप्त होते हैं।

योगेश कुमार गोयल

दुनियाभर में कई देशों की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में भी महासागरों का बहुत बड़ा योगदान है। महासागर खाद्य पदार्थों का प्रमुख स्रोत होने के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक समुद्री और तटीय संसाधनों का वैश्विक स्तर पर बाजार मूल्य प्रतिवर्ष तीन ट्रिलियन डॉलर है। तटीय इलाकों में निवास करने वाले मछुआरों के अलावा समुद्री टूर ऑपरेटरों, लाइफगार्ड, सर्फ प्रशिक्षक, डाइविंग स्कूल, जल क्रीडा तथा बंदरगाह व्यवसाय से जुड़े लोगों और नाविकों को रोजगार भी महासागरों से ही मिलता है। कुछ अध्ययनकर्ताओं का मानना है कि समुद्रों में बढ़ते प्रदूषण और समुद्री जीवों पर इसके दुष्प्रभावों की वजह से समुद्री तटों के आसपास रहने वाले समुदायों को 1.38 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान पहुंच रहा है। 'ओशियन क्लीनअप' नामक संगठन द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक प्लास्टिक समुद्रों में रहने वाली सात सौ से भी ज्यादा जीवों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिनमें से सौ के करीब पहले से ही खतरे में हैं। इसके अलावा समुद्रों में समाते सीवेज तथा अनेक प्रकार के हानिकारक रसायन भी स्थिति को विकराल बना रहे हैं। समुद्रों तथा उनके आसपास रहने वाले लोगों के जीवन तथा आजीविका का मुख्य स्रोत ये समुद्र ही हैं, ऐसे में समुद्रों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा तथा रासायनिक प्रदूषण सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ऐसे में अत्यंत जरूरी है कि समुद्रों का संरक्षण करने और इन्हें प्रदूषण रहित बनाने के लिए पूरी दुनिया में गंभीरता से कदम उठाए जाएं।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते रोजगार के मौके

जयंतीलाल भंडारी

यकीनन देश के बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के मौके भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले माह मई, 2023 में विनिर्माण के लिए पर्चेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) 58.7 पर पहुंच गया। पिछले 31 महीनों में पीएमआई का यह सबसे ऊंचा स्तर है। यह स्पष्ट रेखांकित हो रहा है कि उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं।

हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि सरकार ने सूचना-प्रौद्योगिकी (आईटी) हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना-2.0 को स्वीकृति देते हुए इसके लिए 17,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इस पीएलआई योजना से चीन से अन्यत्र जा रही विश्व की दिग्गज आईटी हार्डवेयर कंपनियों के भारत आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। साथ ही भारत से आईटी हार्डवेयर का निर्यात भी तेजी से बढ़ने का परिदृश्य उभरकर दिखाई दे रहा है।

गौरतलब है कि सरकार ने आईटी हार्डवेयर की इस नई पीएलआई योजना के पिछले स्वरूप के लिए 7,325 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। इस योजना का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और आधुनिक कंप्यूटिंग उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। इस पीएलआई योजना में किए गए नए बदलावों और प्रोत्साहनों से सरकार को उम्मीद है कि तय अवधि में आईटी हार्डवेयर क्षेत्र में 2,430 करोड़ रुपये के निवेश आने के साथ-साथ 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने और उत्पादन मूल्य 3.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का परिदृश्य दिखाई दे सकेगा।

ज्ञातव्य है कि देश में वर्ष 2020 से शुरू हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान में मैन्युफैक्चरिंग के तहत उद्योगों को प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। देश को इस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ाने और चीन से आयात किए जाने वाले दवाई, रसायन और अन्य कच्चे माल का विकल्प तैयार करने के लिए पिछले तीन वर्ष में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत 14 उद्योगों को करीब 1.97 लाख करोड़ रुपये आवंटन के साथ प्रोत्साहन सुनिश्चित किए हैं। पीएलआई योजना के तहत पांच वर्षों में 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 17 फीसदी योगदान देने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करीब 2.73 करोड़ से अधिक श्रमबल के साथ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माता है और तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मोबाइल मार्केट है। भारत का फॉर्मा उद्योग उत्पादित मात्रा के आधार पर दुनिया में तीसरे क्रम पर है। साथ ही भारत दुनिया में सबसे अधिक मांग वाला तीसरा बड़ा विनिर्माण गंतव्य है। इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में लगातार आयात पर निर्भर रहने वाला भारत अब बड़े पैमाने पर इनका निर्यात करने लगा है। देश में ऑटो मोबाइल, फॉर्मा, केमिकल, फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न सेक्टरों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। भारत का वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में 447 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश से बढ़ते हुए मैन्युफैक्चरिंग निर्यात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गतिशील कर रहा है।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रही है। भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए मेक इन इंडिया 2.0, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए तकनीकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए उद्योग 4.0, स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना के लिए पीएम गति शक्ति और उद्योगों को डिजिटल तकनीकी शक्ति प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया जैसी सफल पहलों के कारण। भारत चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियां शोध व नवाचार में आगे बढ़ रही हैं। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर भी उद्योग की ओर से अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के कारगर कार्यान्वयन से वर्ष 2025 तक जीडीपी का 25 फीसदी योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा।

उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा कि देश में स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और वोकल फॉर लोकल मुहिम के प्रसार ने स्थानीय उत्पादों की खरीदी को पहले की तुलना में अधिक समर्थन दिया है और इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भारी प्रोत्साहन मिला है। भारत सस्ती लागत और कार्य कौशल के मद्देनजर विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। 85 देशों के मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित विभिन्न कारकों का समग्र मूल्यांकन करने वाली विश्व प्रसिद्ध 'यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट' 2022 के तहत सस्ते विनिर्माण के मद्देनजर भारत ने चीन और वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए दुनियाभर में सबसे कम 'विनिर्माण लागत' वाले देश का दर्जा हासिल कर लिया है।

नि:संदेह देश में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों का उत्पादन बढ़ रहा है। फुटवियर मेड फ्रॉम लेदर एंड अदर मटेरियल (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर 2022 के तहत देश में एक जुलाई से, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू होने के बाद देश में चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और बंगलादेश से होने वाले घटिया जूते-चप्पलों के आयात में बड़ी कमी आएगी। चीन से सबसे अधिक फुटवियर का आयात होता है। पिछले वित्त वर्ष में 2022-23 में 85.85 करोड़ डॉलर मूल्य के फुटवियर का भारत में आयात किया गया है। अब फुटवियर का घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा व रोजगार बढ़ेंगे। अब चीन से खाद्य संस्करण उत्पादों के आयात में भी कमी आएगी।

वैसे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए अभी मीलों चलना बाकी है। व्यापक नीतिगत सुधारों के तहत सभी उत्पादों के कारोबारों के लिए सिंगल विंडो मंजूरी, इन्फ्रास्ट्रक्चर और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता की पूर्ति के साथ-साथ नई लॉजिस्टिक नीति 2022 और गति शक्ति योजना के कारगर कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा। भारत द्वारा यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को मूर्तरूप दिए जाने के बाद अब यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, कनाडा, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छह देशों, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और इस्राइल के साथ एफटीए के लिए प्रगतिपूर्ण वार्ताओं को तेजी से आगे बढ़ाना होगा। देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चीन और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धी बनाने के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जहां नई श्रम संहिता को शीघ्रतापूर्वक लागू करना होगा, वहीं विभिन्न राज्यों द्वारा फैक्टरीज अधिनियम 1948 में उपयुक्त संशोधन करने होंगे। अब तक कर्नाटक और तमिलनाडु ने फैक्टरीज अधिनियम 1948 में संशोधन करके काम के लिए 12 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी दी है।

मंदसौर गोलीकांड की 6 वीं बरसी पर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद

म.प्र. में चौपट राज, चौपट सरकार, चौपट कर दिया प्रदेश- कमलनाथ

माही की गूंज, मंदसौर/पिपलिया मंडी।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंदसौर गोलीकांड की 6वीं बरसी पर पिपलिया मंडी पहुंचे। कमलनाथ ने कहा, किसान न्याय मांग रहे थे, लेकिन उन पर गोलियां चलीं। 6 वर्ष तक जांच का नाटक चला। आज तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। ये दबाने और छिपाने की राजनीति करें, इसका पर्दाफाश हो चुका है। किसान इनसे अब कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। शिवराज की सरकार चौपट सरकार है। आज एमपी हड़ताल का प्रदेश हो चुका है, जहां देखो वहां हड़ताल हो रही है।

बता दें कि, 6 जून 2017 को किसान आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की मौत हुई थी, जबकि एक किसान की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। चुनावी वर्ष होने से कमलनाथ चुनाव शंखनाद पिपलिया मंडी से कर रहे हैं। कमलनाथ सुबह 10 बजे मंदसौर पहुंचे थे। वे टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर के सामने हाई स्कूल मैदान पिपलिया मंडी में जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से चर्चा करने के बाद कमलनाथ जनसभा को संबोधित करने पिपलिया मंडी पहुंचे।

जनसभा में भारी भीड़ और पेड़ों पर चढ़े लोग

जनसभा में पहुंचे लोगों को देखकर कमलनाथ ने कहा, मैं भगवान पशुपतिनाथ को प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, आपको भी प्रणाम करता हूं। यहां जब भी आता हूं, मुझे मालवा की दाल-बाटी की याद आती है। वो जवानी के दिन थे। जब मालवा में आकर दाल-बाटी खाया करते थे।

कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मैं किसानों को मुआवजा देने आया हूं। शिवराज सिंह ने 18 वर्ष में मप्र को भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया। शिवराज सिंह घोषणा मशीन हैं। आज-कल ये डबल स्पीड में चल रही है। अपनी सरकार में प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। मंदसौर जिले में ही 1 लाख 1 हजार किसानों का कर्ज माफ किया। मंच पर आते ही कमलनाथ ने कहा- मेरा गला खराब है और करीब साढ़े 6 मिनट तक सभा को संबोधित करने के बाद अंत में कहा, सही फैसला कीजिए। डबल इंजन की सरकार प्रदेश का सत्यानाश कर रही है।

कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, चुनाव में 5 महीने बचे हैं और अब उनको किसान, कर्मचारी, व्यापारी सब याद आ गए। ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश का सत्यानाश कर रही है। ये जो शिवराज घोषणाएं करते रहते हैं, ये सब मैं नहीं करता। ये सौदेबाजी की सरकार है। 2018 में जनता ने कांग्रेस को चुना था। सौदेबाजी मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। महाकाल में हवा से मूर्तियां गिर गईं। ये सबसे बड़ा घोटाला है। बीजेपी ने भ्रष्टाचार के लिए महाकाल से भी परहेज नहीं किया।

भाजपा नहीं चाहती कि देश में एक आवाज हो

धर्मांतरण को लेकर कमलनाथ ने कहा ये हिंदू-मुसलमान तनाव पैदा करने के लिए हो रहा है। धर्म राजनीतिक प्रचार का विषय है। भाजपा नहीं चाहती कि देश में एक आवाज हो, क्योंकि एक आवाज सबसे भारी होती है। चुनावी साल में घोषणाओं को लेकर कमलनाथ ने कहा कि हम सोच समझकर पूरा कैलकुलेशन कर घोषणाएं करते हैं, लेकिन बीजेपी फर्जी घोषणाएं करती है।

प्रदेश में एक करोड़ बेरोजगार घूम रहे

पूर्व सीएम ने कहा, प्रदेश में एक करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं। घोषणाएं करी कि 33 लाख करोड़ का निवेश आएगा, इतना तो देश में नहीं आता। कलाकारी और गुमराह करने की राजनीति हो रही है। आज पैसे दो रोजगार दो चल रहा है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट नर्सिंग व्यवस्था, हाईकोर्ट को इसकी आलोचना करनी पड़ी। चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थ व्यवस्था, चौपट नदियां, चौपट सुरक्षा व्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था और चौपट पोषण व्यवस्था।

समर्थन मूल्य की मांग पर आंदोलन कर रहे थे किसान

6 जून 2017 को किसान उपज के दाम एमएसपी मूल्य करने की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे। किसानों का यह आंदोलन पांच दिन से अधिक चला। इस दौरान दूध बंदी, सब्जी बंदी जैसे आंदोलन हुए। इसके बाद किसानों ने सड़कों पर चक्काजाम शुरू किया था। जिले में जगह-जगह किसान हाईवे जाम कर आंदोलन कर रहे थे।

पिपलिया मंडी के पास पार्श्वनाथ तिराहा से लेकर थाने तक किसान सड़क पर बैठे थे। थाने का घेराव किया था। मौके पर पिपलिया मंडी पुलिस और सीआरपीएक के जवान मौजूद थे। किसानों की बढ़ती भीड़ को रोकने पुलिस आगे आई। इसी बीच किसानों और पुलिस बल के बीच झड़प शुरू हुई। पुलिस ने फायरिंग कर दी, इसमें पांच किसानों को गोली लगी, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां सभी ने दम तोड़ दिया।

इसी तरह दलोदा में आंदोलन के दौरान किसान घनश्याम को पुलिस हिरासत में लिया था। उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मौत के बाद शिवराज सरकार ने सभी मृतकों को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। इसके साथ ही घटना की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है।

गरोठ-भानपुरा विधानसभा में अलग ही पहचान बनाने वाले हैं युवा नेता दुर्गेश पटेल

पटेल के नेतृत्व में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा में पहुंचे

माही की गूंज, भानपुरा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मंगलवार 6 जून को मन्दसोर जिले के पिपल्या मण्डी पहुंचे जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव में अब मात्र पांच माह बचे हैं, ऐसे मे संभावित दावेदार हजारो समर्थकों को लेकर अपनी अपनी दमदार उपस्थिति लेकर पूरी ताकत से इस सभा में पहुंचे। सादगी से ओतप्रोत गरोठ-भानपुरा विधानसभा वासियों के सुख-दुख में विगत 2 वर्षों से लगातार सक्रिय रहने वाले प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस नेता दुर्गेश पटेल की क्षेत्र में अलग ही पहचान बनी है। कांग्रेस के हर आयोजन में अपनी अलग छाप छोड़ी है। पिपल्या मंडी में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की सभा में गरोठ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र के प्रदेश युवक कांग्रेस सचिव दुर्गेश पटेल की अगुवाई में 150 कारें, जीपें व 7 बसों के कारवें में लगभग 2 हजार से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्त्ता पहुंचे। दुर्गेश पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्वागत किया, उनके नेतृत्व में अपार उत्साह व जोश देखा गया, पटेल अपने कार्यकर्ताओं की हौंसला अफजाई कर रहे थे। गरोठ भानपुरा से सभी वाहन एक रैली बनाकर सभा में पहुचे।

उल्लेखनीय है कि, राऊ मध्य प्रदेश के रहने वाले युवा दुर्गेश पटेल एम काम तक पढ़े हैं एवं विगत 2 वर्षों से मूल रूप से गरोठ के निवासी होकर पूरी विधानसभा क्षेत्र में जहां भी उन्हें अपने हजारों शुभचिंतकों द्वारा निमंत्रित किया जाता है फिर किसी की शादी ब्याह हो या गमी का माहौल या कोई और अन्य आयोजन सदैव अपनी सादगी से सभी के यहां पहुंचते हैं। ये ही नहीं दुर्गेश पटेल ने युवाओं के साथ घर घर जाकर 1 लाख रुद्राक्ष वितरित किए, वहीं 500 से अधिक बहनों की शादी में यथा योग्य दहेज प्रदान किया। क्षेत्र में क्रिकेट टूर्नामेंट करा कर युवाओं को सक्रिय किया। 2 वर्षों पहले इन्हें यहां कोई नहीं जानता था परंतु उनकी सादगी से भरी लगातार उपस्थिति से लगता है कि वे यहीं के रहने वाले हैं एवं उनमें सेवा भाव की राजनीति का जबरदस्त जूनून है। अब लगातार उनकी सक्रियता से उन्हें गरोठ भानपुरा विधानसभा के आगामी चुनाव में एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है।

अखिल भारतीय जाट महासभा व राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना ने पहलवानों के समर्थन में दिया ज्ञापन

माही की गूंज, शुजालपुर।

अखिल भारतीय जाट महासभा व राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों के समर्थन में जगह जगह राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। साथ ही कुश्ती संघ अ ध्य क्ष ब्रजभूषण शरण सिह की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। बता दे कि, कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिह पर अंतराष्ट्रीय स्तर के खिलाडियो द्वार यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के साथ ही विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। लेकिन आज भी एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस कुश्ती संघ अध्यक्ष ब्रजभूषण शरणसिंह की गिरफ्तारी तक सुनिश्चित नही कर पाई है। साथ ही खिलाड़ियों द्वारा भी ब्रजभूषण सिह की गिरफ्तारी न होने के सम्बंध में राजनीतिक हस्तक्षेप व उनके प्रभाव को बताया जा रहा है। जबकि पोक्सो एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में पहले गिरफ्तारी होती है उसके बाद ही संबधित प्रकरण की जांच की जाती है। अखिल भारतीय तेजवीर सेना द्वारा भी प्रदेश के सभी तहसील व जिला मुख्यालयों पर धरना देकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। साथ ही जल्द गिरफ्तारी न करने पर सरकार के विरुद्ध बड़े आन्दोलन कि चेतावनी दी।

मीडिया से चर्चा करते हुए तेजवीर सेना प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरसिंह जाट ने कहा कि, यह सरकार को तय करना है कि वह एक अपराधी प्रवत्ति के व्यक्ति के साथ खड़ी रहती या पूरे विश्व मे देश का सम्मान बढ़ाने वाली देश की बेटियों के साथ। अगर जल्द ही सरकार द्वारा देश की बेटियों के साथ न्याय नही किया गया तो देश भर में उग्रआंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व पद पर बैठे जिम्मेदार लोगों की होगी।

65 फीट ऊंचे श्रीराम टावर पर लगे स्पीकर से होगा हनुमान चालीसा का पाठ

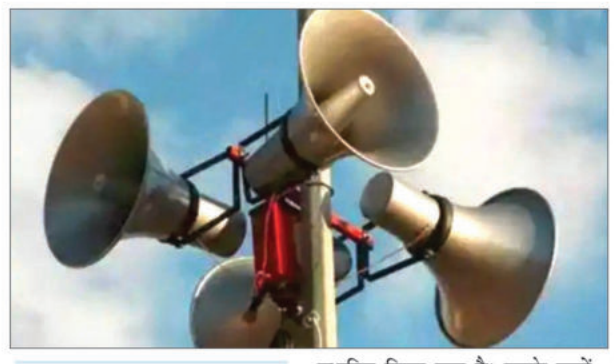

माही की गूंज, गरोठ।

श्रीराम युवा सेना गरोठ द्वारा नगर में 65 फीट ऊंचा श्रीराम टावर स्थापित किया गया है। इसके चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हैं। इससे नगर में हनुमान चालीसा का पाठ सुनाई देगी। टावर का लोकार्पण विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल मालवा प्रांत प्रचारक नंददास दंडोतिया एवं पंडित मिथिलेश नागर के की उपस्थिति में बुधवार सुबह टावर का शुभारंभ किया गया।

पांच लाख रुपए की लागत से निर्मित

श्रीराम टावर से नगर में सुबह व शाम को रामधुन के साथ हनुमान चालीसा का पाठ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ घर-घर तक सुनाई दे इसके लिए पांच लाख रुपए की लागत से नगर के मध्य में श्री सत्यनारायण मंदिर में 65 फीट ऊंचा टावर खड़ा किया गया है। टावर के चारों तरफ लाउडस्पीकर लगे हैं

इंदौर के इंजीनियरों के द्वारा 20 दिन में टावर स्थापित किया गया है। टावर में चारों तरफ लाउडस्पीकर लगे है। टावर की देखरेख श्रीराम सेना करेगी। टावर के शुभारंभ को लेकर शनिवार को श्रीराम सेना द्वारा तैयारियों को लेकर सत्य नाथ मंदिर परिसर में बैठक भी आयोजित हुई थी। नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया सहित श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं को पीले चावल देकर निमंत्रण भी दिया गया था।

आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

माही की गूंज, शाजापुर।

आम आदमी पार्टी मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा की चुनावी तैयारिया कर रही है, जिला कार्यालय पर जिला कमेटी के सदस्यों ने बैठक ली और आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। प्रदेश में प्रदेश स्तरीय आंदोलन का आह्वान किया गया और भाजपा के संविधान विरोधी चेहरे को उजागर किया गया। पूरे प्रदेश में आज प्रदेश स्तर पर आंदोलन और ज्ञापन हुए। इसी कड़ी में शाजापुर में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें भाजपा के दलित और आदिवासी विरोधी होने के साथ संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया।

ज्ञापन में बताया गया कि, संविधान की धारा 79 कहती है कि संसद का मतलब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा है। लेकिन भाजपा दलित आदिवासी समाज को अछूत मानती है और भेदभाव करती है। जिसके उदाहरण हमारे सामने हैं पहला जिसमें राम मंदिर का शिलान्यास हुआ लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। दूसरी बार संसद का जब शिलान्यास हुआ तब भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया जो कि दलित समाज से आते हैं तीसरी बार जब नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन हुआ जिसमें वर्तमान आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। ऐसे में लगता है कि भाजपा तानाशाही शासन चला रही है और आरक्षित समाज का विरोध कर रही है। भाजपा का यह चेहरा अब जग जाहिर है। इसी के साथ नए कार्यकर्ताओ ने सदस्यता भी ग्रहण की। ज्ञापन देने में जियालाला, मनप्रीत सिंह, राजेश सिसनोरिया, गोरधन धानुक, अनिल जाट, डॉ सीपी गोयल, राजपाल, संजय परमार, राधेश्याम मेवाडा, निर्मला सेंगर, दिनेश सेन, रूपेश मेवाडा, शाहबुद्दीन खान मेकेनिक, महोम्मद अंसार, पंकज मालवीय, वहिद खान, हाफिज नियामत खान, राजेश जाटव, अनिल कदम आदि के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मंदसौर गोलीकांड नही हत्याकांड, शिव 'राज' के इशारे पर हुआ मंदसौर हत्याकांड

जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखना चाहते शिवराज

कमलनाथ सरकार बन रही है, एक भी गुनाहगार को छोड़ा नहीं जाएगा- पारस सकलेचा

माही की गूंज, रतलाम।

रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकेलचा 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा पर बुरी तरह हमलावर होते हैं एक के बाद एक बड़े आरोप भ्रष्टचार के लगा रहे हैं। साथ ही प्रमाणित दस्तावेजों के माध्यम से सकेलचा के आरोपो में दम दिखाई दे रहा है जिससे रतलाम में भाजपा लगातार बैकफुट पर जाती दिख रही है। इस बार सकलेचा भाजपा पर मंदसौर गोलीकांड को लेकर मुखर हुए है। उनका सीधा आरोप है कि गोलीकांड के लिए जिम्मेदार अफसरों को शिवराज जी बचा रहे है। इसीलिए जैन आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा जा रहा है। यह आरोप कांग्रेस महासचिव तथा आरोप पत्र समिति उपाध्यक्ष पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने लगाया।

जांच के लिए हुआ था आयोग का गठन, अधिकारीयो के बयान में विरोधाभास

सकलेचा ने कहा कि, 12 जुन 2017 को जैन आयोग का गठन शिवराज ने इस दावे के साथ किया था की एक एक अपराधी को चुन-चुन कर सजा देगे। 13 जुन 2018 को रिपोर्ट आने के 5 वर्ष के बाद भी आयोग की अनुशंसा पर कार्यवाही कर उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा तथा कलेक्टर, एसपी, सीएपी को 8 जून 2017 को सस्पेंड किया था, एक साल में वापस बहाल कर मलाईदार पदों पर रख दिया। इससे सिद्ध होता है की मंदसौर गोलीकांड शिव ÷राज÷ के इशारे पर किया गया हत्याकांड था। सकलेचा ने कहा कि, जैन आयोग में 211 गवाहो के बयान तथा 800 दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि कलेक्टर, एसपी, सीएसपी, एसडीएम, सीआरपीएफ कमांडेंट, थानेदार तथा पुलिस जवानो के बयानो में जमकर विरोधाभाष है। एसडीएम और थानेदार कहते हैं कि, कलेक्टर, एसपी को दोपहर 2 बजे गोली चालन का बता दिया जबकि उनका बयान है कि उन्हें 3:50 बजे अस्पताल में पता चला।

सकलेचा ने बताया कि, बही पार्श्वनाथ चौपाटी तथा पिपलिया मंडी थाने पर जमा भीड़ के बारे में बयान चौंकाने वाला है। 2 से ढाई की भीड़ ने मुंह पर कपड़ा बांधे, हाथों में पत्थर, डंडे, मशाले, तलवार, देसी कट्टे, पिस्टल, पेट्रोल की बोतले, पेट्रोल बम लेकर पुलिस पर हमला किया। जवानों पर पेट्रोल बम फेंके, लगातार फायर किया, पेट्रोल डालकर आग लगाई। पिपलिया मंडी थाने पर पुलिस गाड़ियों में, थाने में आग लगा दी, पुलिस वालो को घसीट घसीट कर पीटा, लात घून्सो से मारा, पुलिस जवान पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। 59 पुलिसवाले घायल हुए। दूसरे दिन जब डॉक्टर गर्ग ने परीक्षण किया तो 32 को छोटा सा गुम्मा तथा 21 को मात्र सूजन आई। डॉक्टर निशांत शर्मा के अनुसार किसी को भी मार्मिक अंग पर कोई चोट नहीं, किसी को भी धारदार हथियार से या आग्नेय शस्त्र से कोई चोट नहीं आई तथा एक भी वाहन नाममात्र का भी नही जला।

सकलेचा ने कहा कि, कैसा आश्चर्य है कि खतरनाक हथियारो से लैस ढाई हजार की भीड लगातार 40 मिनट तक फायर करें, पथराव करें, पेट्रोल बम तथा पेट्रोल की बोतले फेंके, आग लगाये, थाने में घुसकर मारपीट करें, घसीटे, जवानो पर पेट्रोल डालकर आग लगाए, इतना सब होने के बाद एक को भी मार्मिक अंग पर चोट न आए। मात्र पांव, हाथ, पीठ पर एक सेमी का छोटा सा गुम्मा हो या सूजन हो। लेकिन पुलिस हवा मे फायर करे और 5 मर जाए, 6 घायल हो जाए।

गोलीकांड नही बेगुनाह किसानों का हत्याकांड

सकलेचा के अनुसार मंदसौर गोलीकांड नहीं बल्कि सत्ता के इशारों पर बेगुनाह किसानों का हत्याकांड है। अगर जैन आयोग की रिपोर्ट में न्याय नहीं हुआ तो उसे माननीय न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। तथा सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। कमलनाथ सरकार बनने पर इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी।

प्रदेश में रोज होता है 8 लाख लीटर से अधिक दुग्ध संकलन

उपभोक्ता प्रतिदिन खरीदते हैं 7 लाख लीटर से अधिक दूध

माही की गूंज, बड़वानी।

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि, प्रदेश के 6 दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध प्रदायकों से रोज 8 लाख 35 हजार 296 लीटर दूध संकलित किया जाता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और बुंदेलखण्ड दुग्ध संघ द्वारा 6 हजार 593 दुग्ध समितियों के माध्यम से 2 लाख 29 हजार 702 दुग्ध प्रदायकों से यह दूध खरीदा जाता है। इसमें से रोज 7 लाख 16 हजार 465 लीटर दूध उपभोक्ताओं को विक्रय किया जाता है।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि, पशुओं को पौष्टिक आहार मिले और वे स्वस्थ्य रहें, इसके लिये एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा पचामा, मांगलिया, बंडोल, शिवपुरी और सागर में 13 हजार 750 मीट्रिक टन प्रतिमाह उत्पादन क्षमता के पशु आहार संयंत्र संचालित किये जा रहे हैं। गौ-भैंस वंशीय पशुओं को उचित अनुपात में भूसा, चारा और अन्य पौष्टिक आहार खिलाने से पशुओं के शारीरिक विकास के साथ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। दुग्ध संघ के संयंत्रों में निर्मित साँची ब्रॉण्ड सुदाना पशु आहार में विटामिन, प्रोटीन, फेट आदि सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व होते हैं। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है।

पशुओं को हरा चारा निरंतर मिले, इसके लिये दुग्ध समितियों एवं सदस्यों को निर्धारित मात्रा में मौसमवार उन्नत किस्म के चारे के बीज जैसे सूडान-चरी, अफ्रीकनटाल मक्का, बाजरा, मल्टीकट बरसीम, लूसर्न, ओट आदि दिये जाते हैं। इसमें 50 प्रतिशत राशि संघ द्वारा और 25-25 प्रतिशत दुग्ध समितियों और समिति सदस्यों द्वारा वहन की जाती है। अब तक लगभग 155 मीट्रिक टन हरा चारा बीज वितरित किया गया।

कपास की उच्च सघन पद्धति के साथ होगा नए इतिहास का आगाज़

माही की गूंज, खरगोन।

खरगोन सफेद सोने के उत्पादन में पहले ही अपनी पहचान बनाएँ हुए है। अब इस दिशा में खरगोन आगे की ओर कदम बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केन्द्र नागपुर से कपास की तीन ऐसी वैराटियाँ मंगवाई गई है जो सघन पद्धति के लिए उपयुक्त है। ज्ञात हो कि गत वर्ष गोगावां फॉर्मर प्रोड्यूसर ने इसका सफल प्रयोग किया है। अब कृषि विभाग ने भी किसानों के खेतों में सघन पद्धति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर से संपर्क कर वैरायटियों की मांग की थी। कृषि उपसंचालक श्री एमएल चौहान ने बताया कि विभाग को सूरज बीटी (बीएस), रजत बीटी (बीएस) और पिकेवी 081 बीटी (बीएस) और दो अन्य किस्म प्राप्त हुई है। 6 क्विंटल 93 किलो. के साथ खरगोन में एक नए इतिहास की शुरुआत करने जा रहे है। इसके लिए किसानों से विभाग का अमला चर्चा कर प्रेरित करेगा। किसानों को वैराटियों और उत्पादन क्षमता से अवगत करा कर उनकी सहमति से खेतों में प्रदर्शन लगाएंगे।

बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र सभागार में जिले के ग्रामीण कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं का ÷कपास की उन्नत उत्पादन तकनीक÷ विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. जी ए स कुलमी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम क ी रूपरेखा, महत्व एवं आवश्यकता के बारे में सविस्तार अतिथिओं एवं प्रतिभागियों को अवगत कराया। वहीं कृषि उपसंचालक चौहान ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं से कहा कि, वर्त्तमान में कपास की खेती का कार्य किसानों के यहाँ काफी तीव्र गति से चल रहा है। ऐसे में यह प्रशिक्षण सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए लाभप्रद होगा और इसका उपयोग किसानों के बीच सभी विस्तार अधिकारी करे। जिससे किसान इसका लाभ प्राप्त कर सके। कार्यक्रम में डॉ. कुलमी ने कपास की नवीनतम तकनीको जैसे उच्च सघनता प्लांटिंग पद्धति, गुलाबी इल्ली के लिए एसपीएलएटी तकनीक के उपयोग के बारे में बताया गया।

वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह ने समस्त प्रतिभागिओं के समक्ष पीपीटी के माध्यम से ÷कपास में कीट एवं रोग प्रबंधन÷ विषय पर सविस्तार प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनका ज्ञानवर्धन किया। वरिष्ठ तकनीकी सहायक संतोष पटेल ने ÷कपास की उत्पादन तकनीक÷ विषय पर पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. सुनील कुमार त्यागी, तकनीकी अधिकारी विनोद मित्तोलिया, तकनीकी सहायक संतोष पटेल के अतिरिक्त कृषि विभाग के सहायक संचालक पियूष सोलंकी, प्रकाश ठाकुर, दीपक मालवीय सहित कुल 30 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे।

निमाड़ के रत्न का दिल्ली में सम्मान

माही की गूंज, खरगोन।

पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून रविवार को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी राष्ट्र निर्माण में लोगो की भूमिका का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देशभर से 200 से अधिक विद्वत जनों ने भाग लिया। आयोजन में निमाड के शिक्षाविद अखिलेश पाटीदार ने पर्यावरण सुरक्षा एवं अपने प्रयासों को सबके समक्ष रखा। कार्यक्रम में एक विद्यार्थी एक वर्ष एक वृक्ष पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय को अग्रेषित उपरोक्त योजना के फायदे बताकर देश हित मे इसे मील का पत्थर बतलाया। विद्यालय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान जिसमे बच्चे घर मे आ रही पालीथिन से इको ब्रिक्स का निर्माण के रहे है। जिससे वातावरण प्रदूषित होने से बच रहा है। इस अवसर पर निमाड के रत्न अखिलेश पाटीदार का विशेष सम्मान किया गया। शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण , प्रशिक्षण एवम प्रबंधन में अपने विशेष योगदान के लिए विश्व मानव अधिकार सुरक्षा परिषद एवं भारत गौरव रत्न सम्मान परिषद दिल्ली द्वारा भारत गौरव रत्न सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया। पाटीदार विगत 21 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र ने निरन्तर कार्यरत्त है। वर्तमान में पैरामाउंट अकेडमी के प्रचार्य एवं नर्मदा सहोदय स्कूल्स क्लस्टर के सचिव है। साथ ही सीबीएसई के द्वारा खरगोन एवं खंडवा जिले के प्रशिक्षण प्रभारी के तौर पर भी काम कर रहे है। पाटीदार के इस सम्मान पर नगर कर गणमान्य लोगो ने बधाई प्रेषित की।

पूर्व कुलपति डॉ. यादव से मिला लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू का अनुभव

माही की गूंज, बड़वानी।

हमें ऐसा लग रहा था, जैसे हम लोक सेवा आयोग में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। हमसे बहुत स्तरीय प्रष्न पूछे गये। हमारे द्वारा दिये गये उत्तरों का विष्लेषण किया गया। हमें और अधिक पढ़ने तथा रिसर्च करने की प्रेरणा मिली तथा बहुमूल्य मार्गदर्षन मिला। ये बातें फीडबेक देते हुए विद्यार्थीगण सुभाष चैहान, जानकी बर्मन, वर्षा मेहरा, पूनम कुषवाह आदि ने कहीं। दरअसल शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी के स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्षन प्रकोष्ठ के माध्यम से पूर्व कुलपति अवधेष प्रतापसिंह विवि रीवा और इतिहासकार डॉ. षिवनारायण यादव ने विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा ली। कॅरियर सेल प्राचार्य डॉ. दिनेष वर्मा के मार्गदर्षन में कार्यरत है। डॉ. यादव हैं लोक सेवा आयोग के विषेषज्ञ

कार्यकर्तागण प्रीति गुलवानिया और वर्षा मुजाल्दे ने बताया कि डॉ. यादव सर लोक सेवा आयोग के विषेषज्ञ हैं और लोक सेवा आयोग में होने वाले इंटरव्यू में विषेषज्ञ के रूप में शामिल होते रहे हैं। उन्होंने अपने व्यापक ज्ञान और अनुभव से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। लगभग 70 विद्यार्थियों की उन्होंने अलग-अलग समूहों में मौखिक परीक्षा ली और उन्हें महत्वपूर्ण सूत्र बताये। आज विद्यार्थियों से फीडबेक लिया गया। विद्यार्थियों ने कहा कि मौखिक परीक्षा स्तरीय थी, कई प्रष्न कठिन और चुनौतीपूर्ण थे, ऐसा लगा कि वाकई परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। इन बातों का रखें ध्यान डॉ. यादव ने पिछले दिनों मौखिक परीक्षा लेते हुए कहा था कि इंटरव्यू में सफलता के लिए जरूरी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। आपमें आत्मविष्वास रहे। आप प्रष्नों को ध्यान से सुनें और सोचकर सटीक उत्तर दें। वेषभूषा, केषसज्जा आदि अवसर के अनुकूल हो। इंटरव्यू कक्ष में आपका आचरण और व्यवहार सौम्य, शालीन तथा अनुषासित हो तो आपको अवष्य ही सफलता मिलेगी। किसी प्रष्न का उत्तर न पता होने पर मन-गढ़ंत उत्तर देने की अपेक्षा क्षमा मांगते हुए स्पष्ट रूप से असमर्थता व्यक्त कर दें। सहयोग अंकित काग, स्वाति यादव, राहुल भंडोले, दिलीप रावत, डॉ. मधुसूदन ने दिया।

खनिज निरीक्षक ने मुरम उत्खनन करते जेसीबी व ट्रेक्टर को किया जप्त

माही की गूंज, खरगोन। खनिज निरीक्षक श्रीमती प्रियंका अजनार की सूझबूझ से मंगलवार-बुधवार की मध्य रात्रि में अवैध मुरम उत्खनन करते हुए 1 जेसीबी और 4 ट्रेक्टर पर कार्यवाही की गई है। खनिज अधिकारी सावन चौहान ने बताया कि, कलेक्टर शिवराज वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन परिवहन पर लगातार कार्यवाही जारी है। मंगलवार और बुधवार की रात्रि में मुखबिर से लगभग रात्रि 10 बजे कसरावद क्षेत्र के चिचली में जेसीबी से अवैध मुरम की सूचना प्राप्त हुई। खनिज अधिकारी ने अपनी टीम को खनिज निरीक्षक प्रियंका अजनार के नेतृत्व में दल भेजा। खनिज निरीक्षक दल के साथ सीधे मौका स्थल पर पहुँचे जहां एक जेसीबी सरकारी बेड़ी से मुरम का अवैध उत्खनन करते हुए पायी जो चार ट्रेक्टरों में मुरम भर रही थी। टीम द्वारा दोनों को तत्काल जप्त कर रात लगभग 12:30 बजे नज़दिकी पुलिस चोकी खलटक्का की अभिरक्षा में खड़ा करवाया तथा जप्त 01 जेसीबी एमपी 11 जी 5910 तथा 04 ट्रेक्टर बिना नंबर के विरुद्ध मप्र खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

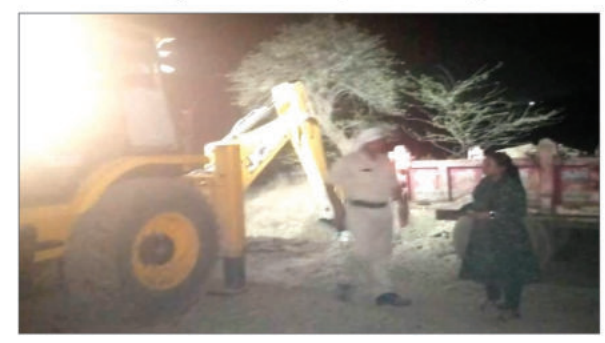

राजपुर में जल प्रदाय परियोजना का कार्य प्रगति पर

माही की गूंज, बड़वानी।

स्वच्छ जल जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वच्छ जल की जरूरत को समझते हुए बड़वानी के राजपुर में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलमपेंट कम्पनी द्वारा जल प्रदाय परियोजना पर कार्य किया जा रहा है।

राजपुर में स्वच्छ जल हर घर पहुँचाने के लिए 1.5 एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र निर्मित किया जा रहा है। वहीं 1 एमएलडी क्षमता का पहले से मौजूद जल शोधन संयंत्र का भी उपयोग किया जायेगा। पहले से मौजूद 700 किलोलीटर और 250 किलोलीटर क्षमता के ओवर टैंक का उपयोग भी जलावर्द्धन योजना में किया जायेगा। राजपुर में हर घर नल कनेक्शन देने का कार्य प्रारंभ हो गया है, 5 हजार 171 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने है जिनमें तीन हजार से अधिक घरों को नल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। 49 किलोमीटर में से 37 किलोमीटर वितरण पाइप लाइन बिछा दी गई है। दस वर्षों के संचालन और संधारण के साथ इस परियोजना की लागत लगभग 29.94 करोड़ रूपये है। इस परियोजना के पूरा होने से राजपुर के रहवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा।

नर्मदा नदी में रेत उत्खनन करते प्रोकलेन और 2 डंपर किए जप्त

माही की गूंज, खरगोन। करही थाना क्षेत्र अंतर्गत पिटामली में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध रेत उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया है। तहसीलदार कैलाश डामोर ने जानकारी देते हुए बताया कि, पुलिस को प्राप्त सूचना के आधार पर तीन विभागों ने कार्रवाई की है। जानकारी अनुसार पुलिस के मुखबिर ने इसकी सूचना दी। इसके बाद कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 2 डंपर और 1 पोकलेन जप्त हुई है। खनिज विभाग द्वारा प्रकरण बनाया गया है। उक्त कार्रवाई में खनिज अधिकारी सावन चौहान, तहसीलदार डामोर, खनिज निरीक्षक श्रीमती रीना पाठक और करही थाना प्रभारी मौजूद रहे।

जिला चिकित्सालय परिसर में अधिकारी कर्मचारियों ने लगाए पौधे

माही की गूंज, खण्डवा।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय खंडवा में सिविल सर्जन डॉ. ओपी जुगतावत वृक्षारोपण किया। इस दौरान आरएमओ डॉ. अनिरुद्ध कौशल, डॉ. अतुल माने, डॉ. राकेश रेवारी, डॉ. मधु तंतवार, डॉ. साकेत ठाकुर एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें अशोक, नीम, बरगद, आंवला एवं अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. जुगतावत द्वारा बताया गया कि स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। देश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए सभी को जागरूक होना अनिवार्य है। पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य अपने चारों तरफ के वातावरण को साफ सुथरा बनाने एवं भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह दिवस खास है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह पेड़ पौधे लगाने में अपना योगदान दें एवं अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें तथा जो पेड़ पौधे हमने लगाए हैं उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी ले।

मूंदी ब्लॉक की मासिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, खण्डवा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शरद हरणे ने बुधवार को विकासखण्ड मूंदी की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमित रुप से सेंवाएं दी जाना सुनिश्चित करें। बैठक में सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, सुपरवाइजर, सीएचओ व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। डॉ. हरणे ने मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु, संस्थागत प्रसव, जननी सुरक्षा, प्रसूति सहायता योजना, आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। साथ ही गर्भवती महिलाओं का गर्भ का पता लगते ही शीघ्र पंजीयन करना और आवश्यक जांच कर उचित उपचार कर अनमोल एप में शत प्रतिशत एंट्री 8 दिवस में पूर्ण करने के निर्देश एएनएम व सीएचओ को दिए। एन.सी.डी. में कम एंट्री व आभा आईडी कम बनने पर सभी सी.एच ओ. को 15 दिवस में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

बैठक में सीएमएचओ डॉ. हरणे ने बीएमओ मूंदी को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रुप से नसबंदी शिविर लगाकर हितग्राही को लाभ दिलाने के निर्देश दिये। साथ ही जिन उपस्वास्थ्य केन्द्रों का टीकाकरण कम है, छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया जाएं व नियमित रुप से सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा कर दिये गये लक्ष्यों की पूर्ति समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में डॉ. हरणे ने बताया कि आगामी दिनों में वर्षाऋतु प्रारंभ होने वाली है जिसे ध्यान में रखते हुए सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक दवाईयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना सुनिश्चित करें। जून माह मलेरिया निरोधक माह के रुप मे मनाया जा रहा है जिसमें डेंगु, मलेरिया की रोकथाम करते हुए लार्वा सर्वे कर लार्वा को नष्ट करें एवं आम जनता को जागरुक करें। इस दौरान मीडिया अधिकारी व्हीएस मण्डलोई, डीपीएम डॉ. शिवराज सिंह चौहान, बीएमओ., जिला टीकाकरण अधकारी डॉ.गिरीराज तोमर एवं अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

नारी सम्मान योजना से प्रदेश की महिलाओं का बढ़ेगा सम्मान - पटेल

विधानसभा क्षेत्र में एक हजार से ज्यादा फार्म का किया पंजीयन

माही की गूंज, जोबट।

जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल एवं नगरपालिका अध्यक्ष सेना पटेल के नेतृत्व में जोबट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अमनकुवा-देवली मे कांग्रेस सरकार की महत्वकांक्षी नारी सम्मान योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में करीब एक हजार 200 से अधिक महिलाओं के नारी सम्मान योजना के फार्म पंजीयन किए गए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रभु प्रकाश राठौड़, सहप्रभारी मधु हिरोडकर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर, पूर्व जिलाध्यक्ष केसरसिंह डावर सहित बड़ी संख्या में महिलाए, कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

कार्यक्रम में महिलाओ में दिख उत्साह

नारी सम्मान योजना को लेकर कार्यक्रम मे आई महिलाओ मे व्यापक उत्साह देखने को मिला, ग्रामीण महिलाएं खुद आगे चलकर फार्म पंजीयन करवा रही थी, उनका उत्साह देखते ही बन रहा था।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि, केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियों से किसान, आदिवासी, दलित एवं पिछड़ा तबका परेशान है, साथ ही कर्मचारी वर्ग भी परेशान है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जनता ने प्रदेश मे कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया हे। प्रदेश मे कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रत्येक महिलाओं को नारी सम्मान योजना के तहत पंद्रह सो रुपए प्रतिमाह और रसोई गैस सिलेंडर पांच सो रूपये में दिया जाएगा। वही कांग्रेस द्वारा 100 रूपये में 100 यूनिट बिजली दी जाएगी। जिला कांग्रेस प्रभारी प्रभु प्रकाश राठौड़ एवं सह प्रभारी मधु हिरोडकर ने कहा की कांग्रेस आदिवासी, दलित, गरीब वर्गो की पार्टी हे, भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है, भाजपा गरीब वर्गों का शोषण करती है। उन्होंने कहा की कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो जाए, आगामी विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष सेना पटेल ने कहा की आज प्रदेश में मातृ शक्तियों पर अत्याचार और अपराध के मामले तेज़ी से बढ़ गए हैं, मामा शिवराज के राज में प्रदेश की बहन, बेटियां और भांजीया सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथजी ने नारी सम्मान योजना लागू कर प्रदेश की महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर एवं कार्यवाहक अध्यक्ष केसरसिंह डावर ने कांग्रेसी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस पार्टी के हित में कार्य करते हुए बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की अपील की। कार्यक्रम मे सहभोज का आयोजन किया गया तथा अंत मे ग्राम मे ग्रामीणों द्वारा मुख्य मार्ग से ढोल-ढमाकों के साथ एक रैली निकाली गई। जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर प्रदेश महिला कांग्रेस संगठन मंत्री रीना चौहान, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष राजेंद्र टवली, आजाद नगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष लईक भाई, कार्यवाहक अध्यक्ष हरीश भाभर, वरिष्ठ नेता मदन डावर, रमिला भूरिया, फिरोज खान, भारता भाई, शोएब खान, सोनू वर्मा, दलसिंह कटारा, दलसिंह परमार, अभयसिंह, मांगीलाल, मयंक सोनी, देवला कटारा, कचनी नलवाया, लता मडीया, दिनेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

अज्ञात शख्स ने गौ माता को किया घायल, श्रीराम गौशाला समिति ने कराया इलाज

माही की गूंज, अलीराजपुर।

गौशाला समिति को सूचना मिली कि नगर के बीच फतेह क्लब के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय के पीछे किसी अज्ञात असामाजिक शख्स द्वारा गौ माता को घायल किया गया है। श्रीराम गौशाला के कर्मठ कार्यकर्ता मनीष गवली घायल गौमाता को देख समिति को सूचना दी। समिति के सदस्यों मौके पे जा कर देखा की गौ माता के पेट पर डेढ़ फीट लम्बा जख्म हैं जो किसी धारदार हथियार द्वारा होना प्रतीत हो रहा था। श्रीराम गौशाला के सदस्यो को गौशाला के अध्यक्ष सुनील राठौड़ द्वारा एकत्रित कर गौमाता को श्री राम गौशाला में लाया गया। जहाँ पर वेटनरी डॉ. ज्ञानेंद्र गेहलोत, डॉ. अल्पेश भाटी, नईमुद्दीन मकरानी ने आकर गौमाता तुरंत इलाज किया। गौमाता के पेट पर 50 से अधीक टांके आए है।

वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि, गौ माता को ठीक होने में 15 से 20 दिन लगेंगे और गौ माता की अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। गौ माता के इलाज करवाने में समिति के सुनील राठौड़, अर्जुन मसानिया, भूपेंद्र माली, संजय गेहलोद, अजय मोदी, विवेक गुप्ता, दिनेश सस्तिया, प्रितेश राठौड़, राजा माली, प्रेम माली, विशाल राठौड़, रूपदेव राठौड़, धर्मेन्द्र शर्मा, पीयूष राठौड़, संस्कार राठौड़, रीतेश राठौड़ आदि सदस्यो का योगदान रहा।

पुरानी नालियों की मरम्मत की मांग फिर उठी जरूरी क्षेत्र में नवीन नालियां भी निर्मित की जाए

माही की गूंज, आम्बुआ।

कस्बे में वार्ड क्रमांक 3 में वर्षों पूर्व बनी नालियों की स्थिति खराब होती जा रही है। हालांकि संपूर्ण कस्बे की नालियां टूट फूट होने के साथ ही नालियों पर किया गया अतिक्रमण भी परेशानी का सबब बना हुआ है।

गूंज प्रतिनिधि को वार्ड क्रमांक 1 के रहवासी शकील कुरेशी, मुकेश प्रजापत, मजीद खां, मोहम्मद खां पठान तथा वार्ड क्रमांक 2 के निवासी दिलीप सिंह ठाकुर, हकीम भाई, फकरु भाई, बद्रीलाल राठौड़ तथा वार्ड क्रमांक 3 के निवासी भरत माहेश्वरी, राजेंद्र राठौड़, सुरेश वाणी, कृष्णकांत जायसवाल तथा वार्ड 4 के असलम खान, अमान पठान, बबलू क्षीरसागर एवं वार्ड 6 एवं 7 के निवासी बाबू सिंह तंवर, मुस्तु भाई, शब्बीर भाई, जितेंद्र सिंह, सलीम खान, अनिल माली आदि ने बताया कि, उनके वार्ड में कई नालियां टूटी पड़ी है। सफाई समय पर नहीं होने के कारण कीचड़ कचरा भरा होकर बदबू मारता है। वहीं वार्ड 3 तथा 6 के मार्ग पर पोस्ट ऑफिस के समीप विगत 3 सालों से नाली के ऊपर बनी रपट टूट जाने के कारण गहरा गड्ढा होकर दुर्घटना को न्योता दे रहा है। वार्ड के पंच भरत महेश्वरी, विशाल माहेश्वरी आदि ने पंचायत को आवेदन दिया जाकर नाली की मरम्मत तथा सफाई की मांग की है।

बता दे कि, नालियों पर अतिक्रमण भी एक समस्या है जिस कारण सफाई कर्मियों को परेशानी हो रही है। मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। इधर घरों का कचरा प्लास्टिक आदि भी नालियों में रहवासी फेंक रहे हैं। जिस कारण नालियां अवरुद्ध हो रही है नागरिकों की मांग है कि टुटी नालियों की मरम्मत तथा जहां जरूरी है वहां नवीन नाली निर्माण कराई जाऐ।

ग्राम पंचायत आम्बुआ सचिव बद्रीलाल भाबौर ने बताया कि, नाली निर्माण एवं मरम्मत हेतु कार्य का प्रस्ताव भेजा गया है। कुछ राशि भी जमा हुई है आहरण हो जाए तो कार्य प्रारंभ कर देंगे।

सातवें वेतनमान के एरियर की क़िस्त के लिए प्रांतीय शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

सातवां वेतनमान पांच सामान किस्तों में दिया जाना है जिसकी चौथी क़िस्त इस वर्ष दी जानी है, इस सम्बंध में लोक संचनालय भोपाल द्वारा आदेश जारी कर 31 मई तक समस्त शिक्षकों को एरियर का भुगतान करने हेतु आदेश भी जारी किया गया। किंतु अभी तक जिले की मात्र तीन-चार संकुलो मे ही चौथी क़िस्त का एरियर प्राप्त हो सका है। सोंडवा विकासखंड सीएसी एवं शिक्षक साथियों ने प्रांतीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश आर वाघेला की उपस्थिति बीईओ सोंडवा वेंकटेश मूर्ति को ज्ञापन सौंपा कर अविलंब एरियर भुगतान की मांग की। जिस पर मूर्ति ने शीघ्र ही विकासखंड के शिक्षको के एरियर भुगतान का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नवीन शिक्षण सत्र में सोंडवा विकासखंड में शाला में छात्रों के प्रवेश, शाला का नियमित संचालन, लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की बात हुई। उपस्थित समस्त शिक्षकों ने नवीन सत्र में उत्साह, उमंग और नई कार्य योजना के साथ सोंडवा विकासखंड को शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी कर नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर दिनेश ठकराला, जितेंद्रसिंह चौहान, गंगाराम, आवस्या, लविंद्र चौहान, कलसिंह डावर, मुवास्या डावर, विजय जमरा, हुकमसिंह वर्मा, चुपसिह निगवाल, कैलाश निगवाल, इंदरसिंह सही सहित बड़ी संख्या में सीएसी एवं शिक्षक उपस्थित थे।

धूमधाम से मनाई जाएगी स्वतंत्रता सेनानी परथी दादा की जयंती

माही की गूंज, बरझर।

आदिवासी समाज जयस 12 जून को स्वतंत्रता सेनानी परथी दादा की जयंती बड़ी धूम धाम से उनकी जन्म भूमि ग्राम पंचायत रिंगोल (मालमसूरी) में मनाएगा। कोर कमेटी ने निर्णय लिया गया है कि, आगामी 12 जून को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परथी दादा की जन्म जयंती है जिसको लेकर तैयारिया तेजी से शुरू हो चुकी है। प्रदेश भर से युवा, बुजुर्ग, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस दादा की जयंती समस्त आदिवासी समाज के साथ बड़ी धूम धाम से मनाई जाएगी। जिसमे सबसे पहले भाबरा त्रिमूर्ति चौराहे पर माल्यार्पण किया जाएगा तत्पच्यात वहा से लगभग 200 से 300 बाइक रैली के साथ रिंगोल पहुंचेगी।

हथनी नदी पूरी तरह सूख कर कंकर पत्थरों का मैदान बनी

माही की गूंज, आम्बुआ।

आम्बुआ-बोरझाड़ के मध्य बहने वाली हथनी नदी जो कि कभी 12 माह तक कल-कल बहती रहती थी, वह आज उस समय सूख रही है। जब पानी की सख्त जरूरत है। नदी के सूखने की प्रमुख वजह क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों से कम वर्षा का होना तथा नदी एवं सहायक नदी नालों पर स्टॉप डेम बैराज तथा तालाब बन जाना भी सूखने का कारण माना जा सकता है।

हथिनी नदी जो कि आजाद नगर भाबरा क्षेत्र के सेजवाड़ा ग्राम के समीप की पहाड़ियों से निकलकर आम्बुआ खड्डाली होकर नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में जाकर ककराना में मिलती है। कुछ वर्षों पूर्व तक यह नदी खुले रूप में बहती थी। जिस कारण आम्बुआ ही नहीं अपितु संपूर्ण नदी क्षेत्र में 12 माह पानी उपलब्ध रहता था बीते वर्षों में इन नदी पर कई स्टॉप डेम बने जिनमें पानी रोका जा रहा है। इसके अलावा इसकी सहायक नदी नालों पर भी स्टाप डेम बैराज तथा तालाब बन जाने के कारण पानी वहां रुक जाने लगा। जब जलाशयों में पूरी क्षमता का पानी भर जाता है तब शेष पानी भरकर नदी में आता है, लेकिन बीते कुछ वर्षों से बारिश कम होने के कारण इसकी सहायक नदी नालों पर बने जलाश्यो का ही पेट नहीं भर पाता है। तब नदी में पानी कहां से आए वर्षा काल में खेतों आदि का पानी नदी में आता है तो नदी में बहाव तेज हो जाता है। लेकिन वर्षा रुकने के बाद पानी कम होने लगता है तथा गर्मी का मौसम आते-आते यह नदी हथनी नदी सूख कर कंक्रीट में तब्दील हो जाती है।

मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन

माही की गूंज, धार।

शासकीय कन्या महाविद्यालय धार में मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन 18 मई से 5 जून तक किया गया। जिसमें महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा सहभागिता की गई। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ सुशील फड़के ने कहा कि सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। अधिक से अधिक संस्था में पेड़ लगाना चाहिए, बिजली बचाए, केम्पस को हराभरा एवं पालीथीन मुक्त रखे। डॉ. सवसिंह चौहान क्रीडा अधिकारी द्वारा वृक्षारोपण एवं रैली का आयोजन किया। जिसमें एनएसएस, एनसीसी एवं इको क्लब की छात्राओं ने सहभागिता की। प्रो. जय कन्नौजे गृह विज्ञान विभाग द्वारा छात्राओं को किचन वाटिका में हरित खाद (कम्पोस्ट)के महत्व के बारे में बताया गया। डॉ. कोमल भाटिया छात्रावास प्रभारी द्वारा छात्राओं को भोजन के दुरूपयोग रोकने हेतु जागरूक किया गया। उन्होने बताया गया कि भोजन को थाली में शेष नही छोड़ना चाहिए। इको क्लब द्वारा आन-लाईन क्लिज पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित किया। जिसमें छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम की सम्पूर्ण जानकारी इको क्लब प्रभारी डॉ. सुनीता मुजाल्दे द्वारा दी गई।

लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों का गांव-गांव एवं वार्ड-वार्ड में किया जा रहा वितरण

माही की गूंज, अलीराजपुर।

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों का जिले में वितरण किया जा रहा है। योजना के स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए पंजीकृत महिलाओं के चेहरों पर खुशियां छा रही है। गांव-गांव एवं फलिया-फलिया में महिला एवं बाल विकास विभाग का मैदानी अमला, अधिकारीगण एवं जन प्रतिनिधिगण के माध्यम से पंजीकृत महिलाओं को उक्त स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को निर्देश दिए है कि प्रत्येक ग्राम स्तर एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों के वितरण की पावती संधारित की जाए। उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारीगण, तहसीलदारगण, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, महिला एवं बाल विकास विभाग डीपीओ एवं सीडीपीओ सहित अन्य अधिकारीगण को रेंडम आधार पर स्वीकृति पत्रों के वितरण का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने निर्देश दिए कि है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्रों के वितरण में किसी भी तरह की कोताही ना हो। इसका विशेष ध्यान दिया जाए। प्रत्येक स्वीकृति पत्रों के वितरण की पावती पंजी में संधारित की जाए।

रोहिंग्या मुस्लिम के शक में 20 को लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जांच में निकले प्रवासी मजदूर

इंदौर।

इंदौर की एक घटना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। इंदौर के एक श्मशान परिसर में कथित रूप से ठहरे 20 लोगों पर कुछ संगठनों ने 'रोहिंग्या मुस्लिम' होने का संदेह जताया। इसके बाद तो यह बात कानाफूसी के जरिए शहर में आग की तरह फैल गई। बात पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस ने एक टीम भेजकर इन लोगों को पकड़ लिया। इन सभी को मंगलवार रात स्थानीय पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये सभी पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर हैं। इसके बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को छोड़ दिया।

पुलिस ने खुद इस वाकए की जानकारी बुधवार को साझा की। एरोड्रम पुलिस थाने की प्रभारी कल्पना चौहान ने बताया कि, कुछ संगठनों की शिकायत पर हमने छोटा बांगड़दा क्षेत्र के एक मुक्तिधाम के पास से करीब 20 लोगों को थाने लाया था। इन सभी लोगों की पहचान के दस्तावेज जांचे गए। सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली गई। छानबीन में ये लोग मूलतः पश्चिम बंगाल के रहने वाले मजदूर निकले। इसके बाद उनको मंगलवार रात ही थाने से जाने की अनुमति दे दी गई।

कल्पना चौहान ने बताया कि, फिलहाल हमें प्रवासी मजदूरों के कब्जे से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला है। थाना प्रभारी ने बताया कि छोटा बांगड़दा क्षेत्र में इंदौर नगर निगम की सीवर लाइन का काम चल रहा है। इस काम के लिए पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को एक स्थानीय ठेकेदार लेकर आया था। उन्होंने बताया कि इन मजदूरों को कथित रूप से श्मशान परिसर में ठहराए जाने पर कुछ संगठनों की आपत्ति के बाद उन्हें ठेकेदार ने अन्य स्थान पर रुकवा दिया है।

प्रवासी मजदूरों को थाने से वापस भेजे जाने के बाद बजरंग दल के स्थानीय संयोजक तन्नू शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि छोटा बांगड़दा के श्मशान परिसर में 15 से 20 'असामाजिक तत्व' पिछले कई दिनों से रुके हुए हैं। तन्नू शर्मा ने संदेह जताया कि ये लोग 'रोहिंग्या मुसलमान' हैं। एरोड्रम पुलिस थाने में सूचना दिए बगैर 'गुप्त रूप से' श्मशान परिसर में रुके हैं। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि इन लोगों के बारे में विस्तृत जांच की जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी।

बाग प्रिंट के बैग बनेंगे जिले की पहचान

माही की गूंज, धार।

जिला प्रशासन धार एवं मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना के अंतर्गत बाग प्रिंट के बैग को धार के सोवेनियर यानी प्रतिक चिन्ह के रूप में पहचान दिलाने की पहल की गई है। धार में स्थानीय महिलाओं एवं युवतियों को बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका शुभारंभ एलआई जी. कॉलोनी धार में किया गया।

वसुधा विकास संस्थान से संकुल समन्वयक मिथुन रावत ने बताया कि, धार की स्थानीय युवतियों एवं महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के उद्देश्य से परियोजना के अंतर्गत निरंतर निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे है। इसी क्रम में बाग प्रिंट के बैग बनाने का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इसमें मुख्य प्रशिक्षक सुश्री सीमा चौधरी द्वारा 2 माह की अवधि मे महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षु महिला स्वरोज़गार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त होगी। साथ ही धार के ऐतिहासिक स्मारकों के ब्लाक से बाग प्रिंट के बैग को धार के सोवेनियर यानी प्रतिक चिन्ह के रूप में पहचान मिलेगी। जिला पुरातत्व , पर्यटन व संस्कृति परिषद धार से तकनीकी सलाहकार गुरुदत्त कांटे ने कहा कि इस प्रशिक्षण में सिलाई के साथ ही प्रशिक्षुओं को बैग डिज़ाइनिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि भी सिखाई जाएगी। महिलाओं के लिए निरंतर नवाचार के माध्यम से आजीविका के लिए रोज़गार सृजन करने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को प्रशिक्षण किट वितरित की गई। सिलाई मशीन का डेमो दिया गया। आभार वसुधा विकास संस्थान से मिथुन रावत ने माना।

विधानसभा का सेमीफाइनल

जिला पंचायत के वार्ड नंबर 9 में चुनाव प्रचार चरम पर

माही की गूंज, खवासा। पवन पाटीदार

थांदला विधानसभा क्षेत्र में खवासा क्षेत्र को अहम इसलिए माना जाता है कि, यही खवासा क्षेत्र के ही मतदाता विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के उम्मीदवार की जीत का फैसला यहीं से होता है। वही जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 9 महिला आरक्षित होकर कांग्रेस व भाजपा को पटखनी देकर जयस समर्थक रेखा निनामा ने जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा थांदला की पांचो जिला पंचायत सदस्य की सीट पर हार का सामना कर चुकी है।

रेखा निनामा सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त होने के बाद जिला पंचायत के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके चलते खवासा क्षेत्र की करीब 20 पंचायतों से जुड़ा इस वार्ड नंबर 9 पर उपचुनाव 13 जून को होगा। वही मतगणना 17 जून को होगी व 19 जून को अधिकृत परिणाम की घोषणा की जाएगी। वैसे तो इस उपचुनाव में 8 उम्मीदवारों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, लेकिन तीन ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस लिए। चुनाव मैदान में ऐसे तो पांच उम्मीद्वार जिसमें भावना संजय निनामा, काली छगन

वसुनिया, पारू बहादुर कटारा, किरण रितेश देवीसिंह देवदा, मीरा बालू वसुनिया चुनावी मैदान में हैं और अपना प्रचार-प्रसार कर पांचो उम्मीद्वार अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस समर्थक काली वसुनिया, भाजपा समर्थक किरण देवदा व जयस समर्थक पारू बहादुर कटारा के मध्य त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। उक्त चुनाव में कांग्रेस अपने बागी उम्मीद्वार मीरा बालू वसुनिया को मनाने में असफल रही। वहीं भावना संजय निनामा को भी कांग्रेस मनाने में असफल रही।

जिसके चलते कांग्रेस मतों का यहां ध्रुवीकरण होता दिखाई दे रहा है लेकिन उक्त चुनाव को थांदला विधानसभा का सेमीफाइनल चुनाव कहां जा रहा है और इसी के चलते यह सीट जीतने के लिए जयस भी फिर से अपनी जीत का दावा कर रही है। वही कांग्रेस किसी भी स्थिति में जीतने के लिए अपना प्रयास कर रही है। इस उपचुनाव समर में भाजपा भी थांदला विधानसभा में जिला पंचायत की सीट पर हर हाल में अपना खाता खोलने के लिए हर प्रयास चुनाव जीतने का कर रही। अब यह 13 जून को ही पता चलेगा कि, मतदाता इस उपचुनाव में किसको जीत दिलाकर झाबुआ की जिला पंचायत कार्यालय में भेजती है।

सीएम राइज स्कूल को अन्यत्र ले जाने की राजनीतिक पंडो की साजिश

दशहरा मैदान के बारे में नगर की जनता को भ्रमित कर रहे राजनीतिक पंडे

माही की गूंज, थांदला। मुकेश भट्ट

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की महती योजना सीएम रायज स्कूल प्रदेश की विशिष्ट योजना में मानी जाती है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं आमजन के लिए इस तरह सीएम राइज स्कूल हर 20 किलोमीटर के दायरे में बच्चों के भविष्य को तय करेंगे। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। थांदला विकासखंड में भी सर्वप्रथम सीएम राइज स्कूल की परमिशन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को मिली थी, किंतु स्थानीय जनप्रतिनिधि को यह संस्था नागवार गुजरी, कारण था कि, आसपास 500 मीटर के अंदर ही एक निजी शैक्षणिक संस्था कार्यरत है जिस पर सीएम राइज का प्रभाव पड़ता, अब बारी आती है उत्कृष्ट विद्यालय की भारी मशक्कत के बाद इसे चयनित कर सीएम राइज स्कूल की आधारशिला रखी गई अब महत्वपूर्ण बात यह है कि, नगर के एकमात्र दशहरा मैदान की जहां पर नगर के समस्त धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम सहित मेला प्रांगण के साथ ही संपूर्ण नगर के बाशिंदों के लिए घूमने, व्यायाम का एकमात्र मैदान है। यह मैदान अब राजनीति पंडो की भेंट चढ़ चुका है, राजनीतिक पंडो ने आखिरी दांव इस मैदान पर खेला है सूत्र बताते हैं कि, मैदान के पीछे 2 विशिष्ट कॉलोनी है व इनका प्रवेश द्वार मैदान ही है। वही मैदान को सरेआम बेइज्जत कर ये पंडे नगर एवम प्रशासन को भी गुमराह कर रहे हैं व सार्वजनिक तौर पर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि, मैदान पूरी तरह से सीएम राइज स्कूल के आगोश में समा जाएगा। दो दिन पूर्व मुख्यमंत्री के झाबुआ आगमन पर भी राजनीतिक पंडों द्वारा शासन एवम प्रशासन को भ्रमित कर संभाग के आला अफसरों को गलत जानकारी दी गई। यहां से सीएम स्कूल को अन्य जगह ट्रांसफर करने का निवेदन किया गया वजह सिर्फ यही कि, कालोनीवासियों के आवागमन का अवैध मार्ग बाधित ना हो।

सीएम राइज स्कूल के निर्माण कार्य की देख-रेख कर रहे विभागीय उपयंत्री आरआर कनेश का कहना है कि, स्कूल भवन निर्माण से मौजूदा खेल मैदान कतई प्रभावित नहीं होगा। नगर में अफवाह फैला कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है जबकि मैदान अपने मौजूदा स्वरूप से कहीं ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा।

इस संदर्भ में नगर की प्रथम नागरिक श्रीमती लक्ष्मी सुनील पण्दा नगर परिषद अध्यक्ष का कहना है कि, यदि कोई खेल मैदान (दशहरा) बचाने की आड़ में सीएम राइज स्कूल को कहीं और ले जाने की बात करता है तो हम उसके पक्ष में नहीं है।

बहरहाल जो भी हो किंतु नगर की राजनीति दशहरा मैदान को लेकर एक ऐसी गंदी राजनीति के दौर से गुजर रही है, जिससे सिर्फ नगर की जनता ही नहीं आने वाले समय में उन नौनिहालों का भविष्य भी दांव पर लगेगा जो आज इस विद्यालय को अन्यत्र ले जाने की बात कर रहे हैं।

अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर कार्य कर रही तहसीलदार मैडम

माही की गूंज, पारा। गजैन्द्र चौहान

बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक अतिक्रमण ने अच्छे खासे पैर पसार रखे हैं। पारा ग्राम में भी ऐसी कोई गली व चौराहा बाकी नही रहा गया है जहां अतिक्रमण नहीं हुआ हो। पहले अतिक्रमण के नाम से पारा पंचायत व जिला प्रशासन ने कई बार अतिक्रमण मुहिम को लेकर कार्रवाई की, लेकिन वर्तमान में स्थति वही ढाक के तीन पात वाली बनी हुई है। अतिक्रमण हटाने के बाद 8 से 10 दिनों में फिर अतिक्रमण हो जाता है।

करीब एक माह पूर्व तहसीलदार मैडम अतिक्रमण की बदौलत लगे जाम में फंस गई थी। दिन गुरुवार था और वो भी हाट का दिन था। सड़क के आस-पास लगी दुकाने व वाहनों से खचाखच भरा बस स्टैंड देखकर मैडम लाल-पीली हो गई और मोके पर पंचायत कर्मचारियों को बुलाकर फटकार लगाते हुए बस स्टैंड पर से अतिक्रमण हटाने को कह गई थी। तभी पंचायतकर्मियों तत्काल हरकत में आकर पक्के सफेद रंग से लाइन खींच कर अपने कार्य की इतिश्री कर दी थी। समय बिता ओर दोबारा तहसीलदार मैडम ग्राम के जाम में नही फंसी, न ही इस ओर ध्यान दिया की अपने द्वारा दिये गए निर्देश का पालन भी हुआ है या नही। जिस दिन खुद जाम में फंसी थी उस दिन नियम कायदे याद आए, जिसके बाद भूल गई। जिससे यह स्पष्ट होता है कि, तहसीलदार मैडम ÷अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता÷ की तर्ज पर निर्देश देकर चली गई। पक्के कलर से खींची लाइन मिटने को आ गई अतिक्रमण नहीं हटा। ठेला व्यवसाय वाले बसों के बीच तो आगे-पीछे ठेला खड़ा कर देते हैं। बस वाले हटाने को कहते हैं तो वाद-विवाद जैसी स्थिति बन जाती है। जब विवाद बढ़ जाता है तो मामला पुलिस चौकी तक पहुंच जाता है स्थिति हमेषा जस की तस ही रहती है।

पार्किंग के आभाव मे ध्वस्त ट्रैफ़िक व्यावस्था

माही की गूंज, पारा।

गांव की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, पार्किंग व्यवस्था के अभाव में लोग बेतुके वाहन बीच सड़क पर खड़े कर इधर-उधर चले जाते हैं। पारा बस स्टैंड से लेकर नीचे शंकर मंदिर प्रांगण तो होली चौक, बोरिंग रोड चौराहा आदि स्थानों पर सैकड़ों वाहन रोजाना खड़े रहते हैं। पारा गांव के अंदर सकरी गलियों में भी दुपहिया वाहनों की अक्सर भीड़ लगी रहती है मैन सड़कों से लेकर अंदर गांव में भी अक्सर जाम जैसी स्थिति बनी रहती है यह तो आड़े दिनों की बात है, गुरुवार हाट बाजार के दिन क्या स्थिति रहती होगी अंदाजा लगाया जा सकता है।

इस मामले को लेकर माही की गूंज ने कई बार समाचार प्रकाशित किये है, मगर कुंभकरण की नींद में सोए जिम्मेदारों के सीर में जूं तक नहीं रेंगती आखिरकार जिम्मेदार कब जागेंगे। दूसरी बात नीचे शंकर मंदिर प्रांगण व स्थानीय बस स्टैंड पर पूरी तरह ट्राफिक व्यवस्था ध्वस्त करने में लंबे रूट की स्लीपर कोच बसें भी कोई कसर नहीं छोड़ती, छोटी बसों से तो पारा का बस स्टैंड खचाखच भर जाता है बाकी बीच में स्लीपर कोच बसें लगाकर और जाम की स्थिति बन जाती है। 8 से 10 स्लीपर बसों का रोजाना आवागमन होता है, इन बसों के पास परमिट है या नहीं यह तो आरटीओ विभाग ही जानता है। इन बसों के कंडक्टर के बीच अक्सर सवारी को लेकर विवाद होता रहता है, कई बार मामला चौकी तक भी पहुंचा।

राजगढ़ नाका पर सीमेंट-सरिया व्यापारी कर रहे लोगों की जान से खिलवाड़

आए दिन होता है यातायात बाधित अधिकारी भी होते है जाम से दो चार

कुछ इस तरह फुटपाथ पर अपना सामान फैला कर स्थाई अतिक्रमण कर रखा है सीमेंट और सरिया व्यापारियों ने।

व्यापारी के यहां खाली होते सीमेंट के ट्राले और यातायात के बीच फंसा एसपी अगम जैन का वाहन।

माही की गूंज, झाबुआ। मुज्जमील मंसुरी

जिला मुख्यालय का व्यस्ततम चौराहा राजगढ़ नाका लगातार पिछले कई सालों से सीमेंट व सरिया व्यापारियों की जद में है। इन सीमेंट-सरिया व्यापारियों की वहज से आए दिन कुछ न कुछ दुर्घटना, घटना या कोई और मामला सुनने में आ ही जाता है। चूंकि राजगढ़ नाका झाबुआ जिला मुख्यालय का एक बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है तो इस पर यातायात का दबाव भी अधिक ही रहता है। रामा, पारा और अलीराजपुर क्षेत्र से आने वाला ट्राफिक सीधे तौर पर इसी चौराहे से होकर गुजरता है। तो नेशनल हाइवे से शहर में आने वाले वाहनों को भी राजगढ़ नाका होते हुए ही शहर में प्रवेश करना पड़ता है। इंदौर और अलीराजपुर जाने वाले यात्री बसें भी इसी चौराहे से होकर गुजरती है। राजगढ़ नाका पर इंदौर रूट की बसों के लिए एक अस्थाई बस स्टैंड है, जहां काफी दिक्कतें पैदा होती है। इसके अलावा राजगढ़ नाके पर बनी रोटरी ज्यादा बड़ी होने से भी यातायात प्रभावित होता है। मगर राजगढ़ नाका पर यातायात में होने वाली दिक्कत का मुख्य कारण यहां पर मुख्य सड़क से सटे सीमेंट-सरिया व्यापारी है। कारण यह है कि, इन व्यापारियों ने खुलेआम फूटपाथ पर अपना कब्जा जमा रखा है और यहीं से वे अपना व्यापार करते है। जिसके कारण राजगढ़ नाका बस स्टॉप के आसपास काफी दिक्कतें आमजन को उठानी पड़ती है। इन व्यापारियों के गोडाउन, दुकान और निवास एक ही होने से यहां आए दिन सीमेंट से भरे बड़े ट्राले सड़क पर ही अनलोडिंग होने के लिए खड़े रहते है। इसके अलावा इन व्यापारियों के यहां सरिये से भरी ट्रकें भी सड़क पर ही खड़े रखकर लोडिंग-अनलोडिंग की जाती है। जिससे यातयात प्रभावित होता है और दुर्घटना का अक्सर ही भय बना रहता है। सीमेंट और सरिये से भरे ट्रकों की वजह से आधा रास्ता बिल्कुल ही अनुपयोगी हो जाता है। इसके अलावा इन्ही व्यापारियों के यहां से लोड होकर जाने वाले वाहन भी सड़क पर ही खड़े कर लोड किए जाते है। सरिया हो या सीमेंट दोनों सामग्री के लोडिंग और अनलोडिंग में रास्ते से गुजरने वाले आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अन्य वाहन चालकों को भी खासी मशक्कत उठानी पड़ती है। जिले में आने वाले नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और जिले के आला अधिकारी भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते है। ऐसा नहीं है कि, इनमें से कोई भी इस समस्या से दो-चार नहीं होता। जिले के आला अधिकारी अक्सर राजगढ़ नाके पर यातायात बाधित होने की समस्या का सामना करते मगर कभी भी इस समस्या के समाधान की ओर इन अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता। यह अधिकारी फंसते-फंसाते इस यातायात की गुत्थम-गुत्था से होकर गुजर जाते, लेकिन कोई भी इन सीमेंट-सरिया व्यापारियों पर ऊंगली उठाने की जुर्रत नहीं दिखाता। नतीजा यह होता कि, अधिकारियों की इस अनदेखी का शिकार आमजनता को होना पड़ता है। इन व्यापारियों को तो सिर्फ अपने धंधे से मतलब रहता। इनके इस व्यापार से किसी को अगर कोई तकलीफ होती है तो उससे इन्हे कोई सरोकर नहीं है। सीमेंट की लोडिंग-अनलोडिंग में उड़ते सीमेंट के कण आमजन के साथ-साथ आसपास के रहवासियों के लिए भी हानिकारक ही साबित हो रहे है। सीमेंट के उड़ते गुबार से दमा और अस्थमा जैसी बिमारियों इन्ही व्यापारियों के कारण निमंत्रण दे रहे है। इसके अलावा सरिये की गाड़ी लोडिंग और अनलोडिंग के कारण लगातार व्यस्ततम मार्ग पर दुर्घटना का भय बना रहता है। ट्रक और ट्रेक्टर-ट्राली से बाहर झूलते लोहे के सरिए हमेंशा ही दुर्घटना को निमंत्रण देते दिखाई पड़ते है। ट्रकों से लोहे के सरिये खाली करवाते समय व्यापारी या उनके मुनीम जरूर सड़क पर दिखाई पड़ते लेकिन यह कतई संभव नहीं है कि, इन लोगों की मौजूदगी भर से दुर्घटना टल जाए। ऐसा नहीं है कि, ट्राली या ट्रक से बाहर झूलते सरियों से कोई हादसा अब तक जिला मुख्यालय पर नहीं हुआ। पिछले दिनों कलेक्टोरेट और न्यायालय परिसर के समीप ही ट्रैक्टर-ट्राली से बाहर झूलते हुए सरिए एक यात्री बस में इस तरह घुस गए थे कि, बस की लोहे की चद्दर फाड़ कर अंदर पहुंच गए और एक यात्री इस घटना में पूरी तरह से घायल हो गया। इस घटना के बाद भी जिला प्रशासन सजग नही हुआ और अब सीमेंट-सरिये के व्यापारी खुलेआम दुर्घटना को न्यौता देते नजर आ रहे है।

इन्ही व्यापारियों का आलम यह है कि, दुकान से कई फिट आगे तक फुटपाथ पर इन्होने कब्जा कर रखा है। ठेठ मेन सड़क के करीब तक इनके सीमेंट के बैग बड़ी संख्या में पड़े रहते है। लोहे के सरियों की भारी फुटपाथ पर पड़ी रहती है। जिससे आमजन को काफी खतरा बना रहता है। इन व्यापारियों के इसी रवैये के कारण आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान है। जब आमजन इस समस्या के खिलाफ व्यापारी से कुछ कहते तो व्यापारी के यहां काम करने वाले मुलाजीम झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है। व्यापारियों का यह झगड़ा आए दिन आसपास के रहवासियों से होता ही रहता है। जिला मुख्यालय पर यूं तो हर बार अतिक्रमण मुहिम चलाई जाती है लेकिन नगरपालिका और प्रशासन की कभी हिम्मत नहीं हुई कि, वे राजगढ़ नाका स्थित इन सीमेंट-सरिया व्यापारियों पर कार्रवाई कर सके। यही कारण है कि, यह व्यापारी खुलेआम दादागिरी से फुटपाथ पर कब्जा कर नोट छापने में लगे हुए है। हाल ही में शहर की उत्कृष्ट सड़क पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है। जिससे एक तरफ की सड़क का यातायात बाधित कर दिया गया है। वहीं दूसरी पट्टी की सड़क पर दोनों ही तरफ का यातायात दबाव बना हुआ है। आने और जाने वाले वाहन एक ही पट्टी का इस्तेमाल कर रहे है। इस स्थिति में भी यह व्यापारी निर्भिक होकर अपना व्यवसाय चला रहे है। उत्कृष्ट सड़क की एक पट्टी बंद होने के बावजूद इन व्यापारियों के यहां वाहनों की भीड़ सड़क पर लग रही है। जिससे यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सीमेंट से भरे ट्राले घंटों यहां खड़े होकर अनलोड हो रहे है तो सरिये की गाडिया इस विकट स्थिति में भी व्यापारी के यहां से लगातार लोड हो रही है। बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे यहां जाम की स्थिति बन गई और इस जाम की स्थिति का शिकार खुद पुलिस अधीक्षक अगम जैन भी हुए। मगर कोई ठोंस कदम उठाने के एसपी साहब अपने सिपाही की मदद से यातायात से निकल कर सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। मानों उन्हे आमजन की इस समस्या से कोई लेना-देना है ही नहीं। उम्मीद करते है कि, जिला प्रशासन इस समस्या को संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाएगा। शहर के व्यस्ततम चौराहे पर बने सीमेंट और सरिये के गोडाउन शहर के बाहर पहुंचाएगें। ताकि आमजन अपने आपको यहां सुरक्षित महसूस कर सके। वैसे तो नियम भी यही कहते है कि, सीमेंट और सरिया व्यापारियों के गोडाउन, शहर के बीच ना होकर शहर से बाहर होना चाहिए। ताकि यातयात भी सुलभ रहे और आमजन को भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

व्यापारियों द्वारा सड़क के बीच में सरिये का ट्रक खड़ा कर अनलोडिंग किया जाता है, राहगिरों व वाहन चालकों को दुर्घटना का भय बना रहता है

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422